+91 7014373732

marudharnews.com

info@marudharnews.com

खबरों और विज्ञापन हेतु संपर्क करे

हिन्दुस्तान की नई आवाज

मरूधर हिन्द

CIN NO.- U74999RJ2020PTC067985
UN NO.- RJ02D0022186

मरुधर हिन्द अब एक नए अंदाज में

वर्ष : 03 | अंक : 177 | जयपुर, रविवार 31 जून 2022 | कुल पेज : 6

छोटी-बड़ी खबरे...

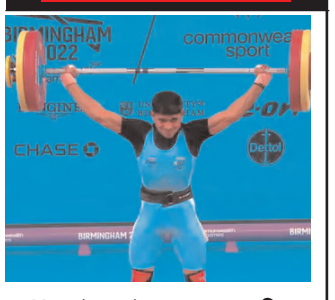

कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन

वेटलिफ्टिंग में भारत ने जीते दो मेडल

संकेत ने सिल्वर और गुरुराजा पुजारी ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया

बर्मिंघम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के मेडल का खाता खुल गया है। वेटलिफ्टर संकेत महादेव ने शनिवार को मेंस 55 केजी वेट कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। मलेशिया के मोहम्मद अनीद ने इस कैटेगरी का गोल्ड जीता। वहीं, मेंस 61 केजी कैटेगरी में गुरुराजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। गोल्ड मलेशिया के अजनील मोहम्मद ने और सिल्वर पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू ने जीता। संकेत ने स्नैच के पहले ही प्रयास में 107 किग्रा का वजन उठा उठाया। उन्होंनें दूसरे प्रयास में 111 किग्रा और तीसरे प्रयास में 113 किग्रा का वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में संकेत ने 135 किग्रा का वजन उठाया है। लेकिन, उनका दूसरा और तीसरा प्रयास विफल रहा। वे 248 किग्रा के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मलेशियाई वेटलिफ्टर ने कुल 249 किग्रा वेट उठाया और सिर्फ 1 किग्रा के अंतर से संकेत से आगे निकल गए।

दूसरी ओर गुरुराजा ने स्नैच में अधिकतम 118 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 151 किग्रा वेट उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 269 किग्रा वेट उठाया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अजनील मोहम्मद 285 किग्रा के साथ पहले और पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू 273 किग्रा के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

बॉक्सिंग- हसमुद्दीन आसान जीत से टॉप-16 में- भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हसमुद्दीन ने 54 किग्रा वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अम्जोलेले दायेयी को 5-0 से हराया।

पहली बार एक मंच पर मोदी-सीजेआई रमनापीएम बोले-ऑनलाइन पेमेंट में भारत सबसे आगे

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला कोर्ट में 1 करोड़ केसों की सुनवाई

नई दिल्ली। भारत में पहली बार हो रहे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अर्थोरिटी मीट में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एक साथ कोई मंच शेयर किया हो। मोदी ने कहा- हमारे गांव-गांव में लोग ऑनलाइन पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुनिया का चालीस फीसदी ऑनलाइन पेमेंट भारत में होता है। इसमें हम सबसे आगे हैं। मोदी ने अपना भाषण श्लोक सुनाकर शुरू किया। वे बोले- अङ्गेन गात्रं नयनेन वक्त्रं न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यं। यानी जिस तरह विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की, नमक से भोजन की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही न्याय से शासन की सार्थकता होती है। हमारे देश सामान्य से सामान्य व्यक्ति को यह विश्वास है, जब कोई नहीं सुनेगा, तब न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये अहसास दिलाता है कि देश उसके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में जिला कोर्ट में एक करोड़ से ज्यादा केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जाते हैं। साठ लाख केस सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में भी सुने गए हैं। यह अच्छा मैसेज है कि हम खुद को लगातार बदल रहे हैं। इसका श्रेय आप सभी को जाता है। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा- आप सभी (जजों) के बीच आना बड़ा सुखद होता है, लेकिन बोलना कठिन हो जाता है।

ज्यादातर लोग मौन रहकर पीड़ा सकते हैं: रमना

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरूकता और आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं। लोगों को सक्षम बनाने में तकनीक की बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने न्यायपालिका से न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने की अपील की।

राजस्थान में युवाओं को नौकरी में दो साल की छूट

सरकार ने एज लिमिट बढ़ाई, केदारनाथ हादसे के पीड़ित परिवारों को भी जॉब

जयपुर। सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को अब अपर एज लिमिट में दो साल की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के कारण सरकारी भर्तियों के लिए दो साल परीक्षाएं नहीं होने का हवाला देकर दो साल की छूट देने की घोषणा की है। राज्य में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये छूट देने का फैसला किया है। बूंदी के हिंडौली में विकास कामों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह में सीएम गहलोत ने कहा कि- 2013 में केदारनाथ हादसे में मरने वाले और लापता लोगों के परिजनों को भी नौकरी दी जाएगी। गहलोत ने सभा के बाद में दोनों घोषणाओं के बारे में ट्वीट भी किए। गहलोत ने कहा कि कोविड के कारण दो साल तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं। इसलिए अगली एग्जामों में कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु सीमा में दो साल की छूट मिलेगी।

511 परिवारों को भी नौकरी

गहलोत ने लिखा- साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी में जान गंवाने वाले और लापता हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजस्थान के ऐसे 511 लोग हैं। अब उन पीड़ित परिवारों से एक एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसे अनुकंपा कैटेगरी का फायदा देकर नौकरी दी जाएगी। इसमें योग्यताओं में छूट मिलती है।

बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था फैसला

सीएम ने कहा- साल 2013 में केदारनाथ हादसे में मरने वालों और लापता राजस्थान के निवासियों को सहारा देने के लिए 2013 में अनुकम्पा नियुक्ति देने की घोषणा की थी। कुछ लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी। सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।

बूंदी में 1133 करोड़ रूपए के कार्यों का शिलान्यास समारोह

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को सभी क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में हाड़ौती के सर्वांगीण विकास के लिए घोषित परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान भी विकास की गति को रूकने नहीं दिया। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, नगरीय विकास व खेलकूद विकास के साथ समाज के सभी कमजोर तबकों को पेंशन, कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसे अनेकों जन कल्याणकारी फैसले लिए गए। अशोक गहलोत शनिवार को बूंदी जिले के हिण्डोली में लगभग 1132.83 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

एनएसए डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 'सर तन से जुदा' नहीं है हमारा नारा

नई दिल्ली। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने शनिवार को ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल के इंटरफेथ सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत की तरक्की को बाधित कर रहे हैं. वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं. इससे पूरे देश के साथ-साथ विदेश में भी इस असर देखने को मिल रहा है. वहीं काउंसिल के अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने एनएसए के सामने कहा, सर तन से जुदा हमारा नारा नहीं है. यह इस्लाम विरोधी नारा है. उन्होंने कहा कि एक एंटी रैडिकल फ्रंट स्क्वॉड बनाया जाए, जिसमें सभी संगठन एक साथ आएं. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत हैं तो उन पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं. नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि दुनिया में एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया है लेकिन अपने देश में हमने घरों को महफूज रखा. उन्होंने कहा कि चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर विवाद खड़ा करते हैं, उसका असर पूरे देश में पड़ता है.

कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाने की जरूरत

नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि जब भी कोई घटना होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाने और उन्हें प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है. चाहे वह कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो, अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.

अगले हफ्ते सोनिया से मिलेंगी ममता

बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की पहल; ईडी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव में आई दरार और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से परेशान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होने की कोशिश में है। इसकी पहल पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी करेंगी। वे 5 दिन के लिए दिल्ली जा रही हैं। उनकी पहल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना राष्ट्र समिति के केसीआर,

सपा नेता अखिलेश यादव, आप नेता अरविंद केजरीवाल और डीएके नेता एमके स्टालिन एक मंच पर आ सकते हैं। इन दलों के लोकसभा में लगभग 125 सांसद हैं। ममता बुधवार को दिल्ली में टीएमसी के सांसदों से मिलेंगी। अगले दिन अन्य दलों के नेताओं से मिलेंगी। शुक्रवार को उनकी सोनिया से मुलाकात होनी है। शनिवार को ममता तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगी। इसी दिन एक लिस्ट भी सार्वजनिक करेंगी। सूत्रों का कहना है कि यह सूची उन नेताओं की होगी, जिनके भाजपा में शामिल होने या अप्रत्यक्ष मदद के लिए राजी होने के बाद उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई थम गई। वहीं, टीएमसी सूत्रों के मुताबिक, शिक्षक घोटाले में करीबी मंत्री और टीएमसी संस्थापक सदस्य पार्थ चटर्जी के करीबी के यहां ईडी के छापे में बरामद रकम से ममता बैकफुट पर थीं।

89.49 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ टॉप पर

सावित्री जिंदल बनीं एशिया की सबसे अमीर महिला, चीन की फैन होंगवी दूसरे

नई दिल्ली।

भारत की सावित्री जिंदल अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सावित्री के पास 89.49 हजार करोड़ रुपए (11.3 अरब डॉलर) की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर चीन की फैन होंगवी हैं। इनके पास भी 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति है। 2021 में एशिया की सबसे अमीर महिला चीन की यांग हुइयान थीं, जो अब तीसरे नंबर पर आ गई हैं। इनकी संपत्ति 87.11 हजार करोड़ (11 अरब डॉलर) है।

ब्लूमबर्ग की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में सावित्री 164 वें स्थान पर पहुंच गई हैं। बता दें कि गौतम अडाणी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनके पास 9.35 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। कंपनी भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करती है।

कभी नहीं गईं कॉलेज

एक रिपोर्ट के अनुसार, सावित्री जिंदल कभी कॉलेज नहीं गई। इसके बावजूद पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने ही पूरा कारोबार संभाला। वे कहती हैं कि जिंदल परिवार में अधिकतर महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। जबकि पुरुष बाहर के काम देखते हैं। इसके चलते सावित्री को अपने पति का कारोबार संभालने में काफी मेहनत करनी पड़ी। सावित्री देवी 1950 में असम के तिनसुकिया में पैदा हुई। 1970 में जिंदल ग्रुप के फाउंडर हरियाणा के ओमप्रकाश जिंदल से उनकी शादी हुई। जिंदल ग्रुप स्टील के साथ और कई सेक्टर में एक्टिव है। ओपी जिंदल और सावित्री के नौ बच्चे हैं। चार बेटे- पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन, रतन और नवीन हैं। सबसे बड़े बेटे पृथ्वीराज, जिंदल सॉ कंपनी के चेयरमैन हैं। दूसरे बेटे सज्जन जिंदल ने JWS कंपनी की कमान संभाल रखी है। तीसरे बेटे रतन कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं।

बीजेपी जुटी 2023 चुनावों में, प्रदेशाध्यक्ष का बाड़मेर दौरा:जिलाध्यक्ष बोले- बूथ, मंडल और पन्ना प्रमुख के माध्यम से जीतेंगे

बाड़मेर। बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं आमेर विधायक सतीश पूनिया लगातार दौरे कर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की नब्ज टटोल रहे हैं। फिलहाल जोधपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे। दो दिवसीय प्रोग्राम के तहत 2 अगस्त को बाड़मेर आएंगे। बीजेपी ने दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के साथ मंडल, अलग-अलग मोर्चा का फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी राजस्थान में फिलहाल पन्ना प्रमुख पर फोकस कर रही है।

दरअसल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया जैसलमेर से 2 अगस्त को 11 बजे बाड़मेर आएंगे। बाड़मेर-जैसलमेर जिले की सीमा के गांव बरियाड़ा पर जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसी दिन 11 बजे कैलाश इंटरनेशनल में बीजेपी के अलग-अलग श्रेणी कार्यकर्ता है उनके साथ संगठनात्मक समीक्षा बैठक रखी गई है। पूरे दिन तक कार्यकर्ताओ व पदाधिकारी के साथ मैराथन मीटिंग लेंगे। बैठक में फोटो युक्त बूथ समिति व पन्ना प्रमुख, मोर्चा, प्रकोष्ठ व विभाग संरचना, मण्डल व शक्ति केंद्र संयोजक संरचना, बूथ सशक्तिकरण व जिला मंडलों की बैठकों पर चर्चा व समीक्षा की जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल के मुताबिक वोटर लिस्ट के एक पन्ने के मुताबिक पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। जिले के पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष जहां वोटर लिस्ट में नाम है उस वोटर लिस्ट पेपर का प्रमुख होगा। वोटर लिस्ट के एक पन्ने में 60 लोगों से संवाद करना उनसे फीडबैक लेने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होगी। हम सक्रिय बूथ समिति, सशक्त मंडल और पन्ना प्रमुख के माध्यम से 2023 व 24 के चुनावों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। संगठनात्मक बैठक होने के बाद जनप्रतिनिधि, समाज के प्रमुख लोग इन सबसे प्रदेशाध्यक्ष संवाद करेंगे। कई लोग बीजेपी में शामिल भी होंगे।

आखिर.. केजरीवाल सरकार ने वापस ली नई शराब नीति

मनीष सिसोदिया पर 144 करोड़ के हेरफेर का आरोप, एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि राजधानी में 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में सीबीआई की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।

उप राज्यपाल ने दिए थे सीबीआई जांच के निर्देश

दिल्ली के उप राज्यपाल ने नई शराब नीति के बाद निकले टेंडर को लेकर सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया कि सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंस धारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया।

संसद में 10 दिन में टैक्सपेयर्स के 100 करोड़ खर्च

दोनों सदनों में 120 घंटे की जगह 26.8 घंटे काम हुआ, सिर्फ दो बिल पास

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र हंगामे के कारण चल ही नहीं पा रहा है। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के पहले दो हफ्तों में कभी विपक्ष तो कभी सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा और राज्यसभा में इन दो हफ्तों में 60-60 घंटे यानी 120 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा 15.7 घंटे और राज्यसभा में 11.1 घंटे यानी कुछ 26.8 घंटे ही काम हुआ। मानसून सत्र में सरकार ने दोनों सदनों में 32 बिल पेश करने का ऐलान किया था। अब तक टैक्सपेयर के करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद सिर्फ दो ही बिल पास हो पाए हैं। ये दोनों ही बिल लोकसभा से पास हुए हैं। राज्यसभा से एक भी बिल पास नहीं हुआ है। 30 बिल अब भी बाकी हैं।

मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ के मुद्दे पर हमलावर रहा तो सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर दिए गए विवादित बयान पर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में कामकाज रोककर अग्निपथ पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई।

100 करोड़ कैसे बर्बाद हुए

संसद में हफ्ते में पांच दिन काम होता है। रोज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सदन चलती है, इसमें एक घंटे का लंच ब्रेक होता है। यानी एक दिन में 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। साल 2018 में लोकसभा सचिवालय की रिपोर्ट के अनुसार सदन चलाने में हर घंटे 1.6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तब से अब तक चार साल में महंगाई बढ़ी है। लेकिन, 2018 की रिपोर्ट के ही आधार पर चलें तो सदन चलाने का एक दिन का खर्च करीब दस करोड़ रुपए आता है। मानसून सत्र के पहले दो हफ्तों में दस दिन की कार्यवाही में इस हिसाब से करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए।

हंगामों के बीच लोकसभा में अंटार्कटिका बिल और परिवार न्यायालय संशोधन बिल पास जरूर किया गया, लेकिन अन्य बिलों पर चर्चा ही नहीं हो सकी। राज्यसभा में एक भी बिल पास नहीं हुआ।

शाहजहांपुर आबकारी पुलिस की कार्रवाई

करीबन 33लाख रुपये की दिल्ली मार्का की शराब पकड़ी

मरूधर हिंद

शाहजहांपुर। आबकारी थाना पुलिस शाहजहांपुर ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर अल सुबह करीबन 33लाख रूपये की दिल्ली मार्का की शराब दिल्ली से गुजरात जाते समय टोल प्लाजा पर शराब बरामद कर चालक वीरमाराम पुत्र भभूताराम निवासी दूदू को गिरफ्तार किया।

शाहजहांपुर आबकारी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली की दिल्ली से गुजरात के लिए ट्रक के जरिए अवैध अंग्रेजी ब्रांड की शराब ले जाई जा रही है ।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच की गई। जिसमें गुजरात नंबर के कंटेनर को रुकवाकर चेक किया तो कंटेनर में शराब भरी हुई मिली। पुलिस ने कंटेनर को जप्त कर थाने पर लाकर शराब उतरवाई गई ।546 कार्टून जिसमे रॉयल चलेंग के 70कार्टून, मेकडोल 422 कार्टून,54कार्टून अन्य ब्रांड की शराब बरामद की है।वही यह थाना पुलिस की दूसरी बड़ी कार्यवाही है।

नंगली बलाहीर में बाबा थाडेसर महाराज का भव्य मेला

नीमराना

उपखंड क्षेत्र के गांव नंगली बलाहीर में थाडेसर महाराज का भव्य मेला एवं कुश्ती दंगल एवं कबड्डी, हाई जंप, लॉन्ग जंप तथा गोला फेंक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान प्रदेश सहसंयोजक प्रशिक्षण डॉ शानू राजकुमार यादव ने मेला का उद्घाटन किया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्यनारायण शर्मा भी उपस्थित रहे। डॉ शानू यादव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा की आप सबका खेल के प्रति उत्साह देखते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है । ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की की प्रतियोगिताएं खेल में निखार लगता है और प्रतिभा को आगे आने का मौका मिलता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा की सभी खिलाड़ी न सिर्फ नीमराना,बहरोड़ और राजस्थान बल्कि देश का नाम विश्व पटल पर रौशन करें और इसके लिए हमेशा तैयारी करते रहे और हम हमेशा साथ खड़े हैं। आयोजन कर्ताओं को इस तरह के कार्यक्रम को निरंतर आयोजन करने को प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम सरपंच राजबाला पूरन सिंह,पूर्ण भगत,महेश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहें।

विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विधालय कुशलगढ में खेल दिवस का आयोजन

कुशलगढ़ से अरुण जोशी की रिपोर्ट

कुशलगढ़। विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विधालय कुशलगढ में खेल दिवस का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न खेल समुह शिशु, बाल,किशोर कक्षा 1से5 ,6 से8 व9,10 कक्षाओं के भया बहिनो ने भाग लिया ,कबड्डी, खो खो, ऊँची कुद,लम्बी कुद ,गोला फेक एथलेटिक्स में विभिन्न दड का आयोजन हुआ।विधालय के प्रधानाचार्य कैलाश राव नेभया बहिनो को अपने सम्बोधन में कह की आगामी माह में संकुल व जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा उसमे हमे विजेता बन कर प्रांत में जाना है। आपने कहा की खेलो से भैया बहिनो के जीवन में अनुशासन आता हैं वह स्वस्थ रहता हैं खेल शारिरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। विधा भारती बालक का सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत हैं। खेल प्रभारी रुपसिह ने विधालय स्तर पर बनी टीम की घोषणा की इन्हें सहयोग देने में हिम्मत सिह ,अक्षिता दीदी, स्वागत जी ,निर्देश जीआदि उपस्थित रहे।आभारा प्राथमिक के प्रधानाचार्य परेश बुनकर ने माना।

क्यों न खनन पट्टों को निरस्त कर दिया जाए , लीज धारकों को नोटिस जारी कर 15 दिवस व मांगा जवाब

मरुधर हिंद /आमिर खान कामां

कामां-ब्रज के दिव्य पर्वतों आदिबद्री व कनकांचल पर्वतों की रक्षा के लिए साधु विजयदास द्वारा अपने प्राणों की आहुति दिए जाने के बाद अब सरकार भी संतों की मांग पर पर्वतो को संरक्षित कर खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सक्रिय हो गई है जिसके तहत खॉन व पेट्रोलियम मंत्रालय की उप शासन सचिव नीतू बारूपाल ने लीज धारकों को नोटिस जारी किया है। खान व पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लीज धारकों को भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि आदिबद्री व कनकांचल पर्वत को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है यह दोनों पर्वत ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आते हैं इसलिए परिक्रमार्थियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा ,पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में फैले पर्यावरण प्रदूषण पर रोकने व आमजन के स्वास्थ्य को मध्य नजर रखते हुए के लिए इन पर्वतो पर अब खनन गतिविधियां पूरी तरह से बंद की जानी है तो क्यों ना इन दोनो पर्वतो में संचालित लीजो के खननपट्टो निरस्त कर दिया जाए नोटिस में लीज धारकों को 15 दिन का समय देते हुए खान विभाग के उप शासन सचिव कार्यालय में अपना पक्ष रखने को कहा गया है नोटिस में यह भी लिखा गया है यदि 15 दिवस में लीज धारक नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो लीज समाप्त करने की दिशा में उनकी सहमति ही समझी जाएगी वहीं दूसरी ओर नोटिस मिलने के बाद खनन पट्टा धारकों ने अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों से कानूनी सलाह मशविरा शुरू कर दिया है और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा बना रहे हैं लीज धारकों का कहना है कि यदि सरकार इन पर्वतों को वन संरक्षित घोषित कर चुकी है खनन गतिविधियां बंद करना चाहती है और सरकार अपने द्वारा जारी किए हुए खनन पट्टों को निरस्त करना चाहती है तो लीज धारको के हित का भी ध्यान रखते हुए अन्यत्र पहाड़ो में इन लीजों की एवज में दूसरी खान लीज आवंटित करें लीज धारको का कहना है कि हजारों श्रमिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो गए हैं सरकार को उनके रोजगार की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक गिरफ्तार

मरुधर हिन्द/रमाकान्त शर्मा

बानसूर -घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में रामकरण गुर्जर (गोदाराम)पुत्र हनुमान सहाय गुर्जर निवासी बास दयाल को गिरफ्तार किया गया। बानसूर पुलिस ने बताया कि युवक पर पहले भी मारपीट, लूटपाट व सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के विरुद्ध मामले दर्ज हैं। वहीं कुछ माह पूर्व युवक के खिलाफ एक महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया था जिसको लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

नीमराणा वीआईपी स्कूल के बस चालक व परिचालक की लापरवाही ने ली एक वृद्ध की जान

ग्रामीणों में रोष प्रदर्शन, मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन

मरुधर हिन्द/ हवासिंह चौधरी

मुंडावर। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंडनावाडा कलां के गांव सहजादपुर में वीआईपी स्कूल बस के ड्राइवर व कैंडेक्टर की लापरवाही से पीछे से राह चलते वृद्ध को बस बैक करते हुए टक्कर मार दी। स्कूल बस की टक्कर से जरमल पुत्र श्रीचंद निवासी सहजादपुर उम्र करीब 68 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई । प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नीमराणा की वीआईपी स्कूल की बाल वाहिनी के ड्राइवर व परिचालक ने लापरवाही से बस को चलाते हुए बैक करने पर राह पर चलते हुए राहगीर को पीछे से टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही राहगीर की मौत हो गई। गनीमत रही कि बाल वाहिनी में बैठे बच्चों को नुकसान नहीं हुआ।

मौके पर मौजूद भीड़ ने पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग से निजी बाल वाहिनियों के चालकों की

जांच करने सहित हरियाणा राज्य से आ रही बाल वाहिनियों की भी जांच करने की मांग की ।

सूचना पर मुंडनवाडा कलां सरपंच दिलीप यादव, जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा एवं मुंडावर थानाधिकारी संजय शर्मा मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे।

थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि नीमराना स्तित वी आई पी स्कूल के बस चालक और परिचालक की लापरवाही से 30जुलाई को सुबह सहजादपुर में एक वृद्ध को टक्कर मार दी गई जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई जिसको लेकर ग्रामीणों ने स्कूल बस को चालक सहित रोक लिया व पुलिस को सूचना दी गई और मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की जिस पर सरपंच दलीप यादव, वीरू सरपंच व थाना अधिकारी संजय शर्मा की मौजूदगी में स्कूल संचालक द्वारा आठ लाख रुपए मुआवजा व मृतक के पोतो को निशुल्क स्कूल में पढ़ाए जाने पर ग्रामीणों की सहमति हुई उसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मुण्डावर मोर्चरी में भिजवा दिया।पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा।

स्मृतिस्वरूप मिनी रक्तदान शिविर का आयोजन व स्कूल में बैग वितरण

कुशलगढ़ से अरुण जोशी की रिपोर्ट

बांसवाड़ा- एक समय रक्तदान जनजागरण की कमी से अक्सर लोग रक्तदान से हिचकते थे। जिसके कारण ब्लड बैंक में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परन्तु धीरे धीरे क्षेत्र में सपना फाउंडेशन द्वारा जनजागरण के लिए किए जा रहे प्रयास दिखने लगे है।अब ज़िले के दूर दराज क्षेत्रो से आकर रक्तवीर रक्तदान कर रहे है। हर घर रक्तवीर की सफ़लता से रौशन होता वागड़ कुछ समय पहले सपना फाउंडेशन द्वारा हर घर रक्तवीर की एक पहल शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य था की वागड़ के हर घर तक रक्तदान की चर्चा पहुँचाई जाए ऐसे में इस पहल से कुछ ऐसे परिवार जुड़ गए जो रक्तदान से ही श्रद्धांजलि व जन्मदिन जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे है।

इसी कड़ी में आदर्श परिवार के रूप में सपना फाउंडेशन के सदस्य यादव ट्रेडर्स बाँसवाड़ा समूह द्वारा स्व. कांतिलाल यादव की द्वितीय पुण्यतिथि की

स्मृति में ब्लड़ बैंक पहुचकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दे कि यादव ट्रेडर्स द्वारा लगातार दूसरी बार यह रक्तदान शिविर का आयोजन स्मृतिस्वरूप रखा गया । शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीर कंकु देवी, उमेश यादव, नरेश यादव, दीपक यादव, जितेंद्र यादव, जतिन यादव, प्रिंस यादव, विट्ठल यादव, योगेश राठौर, नयन चौहान व साथ ही रूधिर फाउंडेशन से गौरव भोई, पंकज यादव ने रक्तदान किया गया।

रक्त की कमी सम्बन्धी जानकारी के बाद एक साथ रक्तदान

यादव ट्रेडर्स से नरेश यादव ने बताया की स्मृतिस्वरूप रक्तदान का यह सेवाकार्य ही है जो किसी जरूरतमंद को नया जीवन देगा अतः आमजन को अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

उंन्होने कहा कि सोशल मीडिया से सूचना मिल रही थी कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी है। साथ ही परिवार के सदस्यों द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाल रन्धावा में बैग एवं फल वितरित किये गए। इस दौरान सपना फाउंडेशन से कांतिलाल यादव शिवपुरा व धर्मेश यादव, प्रकाश यादव, महेश यादव उपस्थित रहे। ये जानकारी विश्वभर मेघवाल ने दी।

लायंस क्लब बहरोड़ किंग्स के द्वारा प्रथम बार तीज सिंधारा महोत्सव का आयोजन का किया गया

मरुधर हिन्द/हवासिंह चौधरी

बहरोड़ । लायंस क्लब बहरोड़ किंग्स के द्वारा 30 जुलाई को शहर के प्रमुख होटल होटल हाईवे एक्सप्रेस नवीन परिसर में तीज सिंधारा महोत्सव का आयोजन किया गया ।

लायंस क्लब बहरोड़ किंग्स के द्वारा प्रथम बार इस तरह के महोत्सव का आयोजन का किया गया।

जिसमें लायंस क्लब बहरोड़ किंग्स परिवार की सभी लायन महिला सदस्यों व बच्चों ने भाग लिया । इस अवसर पर उपस्थित रही सभी महिलाओं ने एक दूसरे से परिचय किया संवाद किया आगामी सभी प्रकार की होने वाली सेवा गतिविधियों पर विचार किया व एक दूसरे के परस्पर सहयोग हेतु भी विचार किया । महोत्सव के दौरान लायन महिला सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के खेलों , क्रिज प्रतियोगिता , डांस प्रतियोगिता व म्यूजिक कार्यक्रम का आयोजन किया । सभी गतिविधियों में विजेता रही महिलाओं व बच्चों को प्रथम द्वितीय व तृतीय प्रकार पुरस्कारों से नवाजा गया ।

इस अवसर पर लायन अध्यक्ष लायन राकेश

रोहिल्ला ने सभी महिला आगंतुक सदस्यों का स्वागत किया । एक दूसरे को तीन सितारा महोत्सव की बधाई देते हुए सभी ने कार्यक्रम का लुफ्त उठाया ।

साथ ही संबोधित करते हुए लायंस क्लब मेंबरशिप चेयरमैन लायन प्रमोद अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों को क्लब के द्वारा निरंतर रूप से करते रहना चाहिए व महिला सदस्यों को भी समाज के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा को दोहराते भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए ।

तीज सींधारा महोत्सव में लायन नीतू रोहिल्ला बीना अग्रवाल अन्नु अग्रवाल बुगलेश यादव सीमा अग्रवाल शीतल दीवान सीमा गुप्ता डॉक्टर ज्योति अग्रवाल कोमल सोनी सांची अग्रवाल मोनिका सरिता अग्रवाल नीतू गुप्ता मधुबाला गुप्ता पिंकी जयसवाल कशिश बंसल आदि महिला सदस्यों सहित मुकेश यादव दिनेश अग्रवाल मनीष गुप्ता नवीन गोयल नीरज सोनी उपस्थित रहे ।

जिंदल ब्रांड के नाम से पकड़ी नकली फैक्ट्री, मैनेजर गिरफ्तार, मालिक फरार

विश्वकर्मा थाना प्रभारी रमेश सैनी की बड़ी कार्रवाई

हरमाड़ा/सीपी गहलोत।

जयपुर शहर में ब्रांडेड कंपनी जिंदल के नाम से नकली फैक्ट्री पकड़ी गई है। विश्वकर्मा इलाके में यह नकली फैक्ट्री पकड़ी गई है। जहां जिंदल के नाम से नकली लोहे के टीनशेड का निर्माण व व्यापार होता था। पुलिस ने मौके से मैनेजर सुरेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। फरार मालिक मोहित जैन की तलाश जारी है।पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम वंदिता राणा ने बताया कि जयपुर के विश्वकर्मा में जिंदल के नाम से फर्जी फैक्ट्री चल रही थी। इसकी सूचना मैसर्स ब्राण्ड प्रोटेक्शन प्राईवेट लिमिटेड जासोला दिल्ली के आपरेशन मैनेजर गौरव श्रीवास्तव व फील्ड आफिसर संजय वर्मा ने विश्वकर्मा थानाधिकारी रमेश सैनी को दी। इसके बाद नकली फैक्ट्री पर दबिश देने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। शनिवार दोपहर में विश्वकर्मा के रोड नंबर 6 पर स्थित अरिहंत स्टील्स पर पुलिस ने छापा मारा। जहां से पुलिस ने लगभग 20 टन नकली टीनशेड, जिंदल ब्रांड नाम अंकित करने वाली लेजर मशीन को जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मालिक मोहित जैन अपने मैनेजर

सुरेंद्र कुमार के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा कर रहा था। बाजार में जिंदल के नाम से बने नकली टीनशेड को असली बताकर बेचा जा रहा था। ग्राहक ब्रांडेड कंपनी का टीनशेड समझकर खरीद लेता था। इस तरह आरोपी मोटा मुनाफा कमा रहे थे। वहीं, पुलिस इस मामले में आरोपी मैनेजर सुरेंद्र कुमार शर्मा से पूछताछ में जुटी है।

कुशलगढ़ के रेफरल चिकित्सालय का रोटरी क्लब के पदाधिकारीयो ने अस्पताल का निरीक्षण किया

कुशलगढ़ से अरुण जोशी की रिपोर्ट

कुशलगढ़ आज रेफरल चिकित्सालय में कुशलगढ़ रोटरी क्लब के पदाधिकारी और सदस्य बीमार वालों की भीड़ को देखकर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे जहां पर अस्पताल में कई अनियमितता पाई गई जिस पर सदस्यों ने व्यवस्था सुधारने की डाक्टरों से बातचीत कर कहा पदाधिकारियों ने कहा की दवाइयां अस्तव्यस्त पड़ी है जिन्हें एक व्यवस्थित रखी जाए सोनोग्राफी मशीन चालू कराई जाए एम ऑक्सीजन लाइन डालने के बाद भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है जिसको भी चालू करने की मांग की और लोगों को सभी प्रकार की अस्पताल में सुविधा उपलब्ध कराई जाए रोटरी क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य मंत्री को कुशलगढ़ अस्पताल की व्यवस्था के बारे में ज्ञापन देकर संसाधन उपलब्ध कराएंगे। रोटरी क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा उपाध्यक्ष अर्पण चोपड़ा पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गादीया यश खाबिया, पंकज लुणावत मनोहर कावडीया एडवोकेट हरेंद्र पाठक पंकज लुणावत,रोनक सेठ, रितेश बम सहित रोटरी क्लब के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

भरतपुर सांसद ने कठूमर विधानसभा में अपने दो प्रतिनिधि किए नियुक्त

मरूधर हिन्द

कठूमर।दिनेश लेखी। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने कठूमर विधानसभा मे? अपनी ओर से प्रतिनिधी नियुक्त किये है। सांसद ने बताया विधानसभा कठूमर की समस्याओ के शीघ्र समाधान के लिये भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा और कठूमर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज को प्रतिनिधी नियुक्त किया है।

इधर राजकुमार पंडा ने बताया कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता है। ब्राह्मण समाज में कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। जनता के लोकप्रिय नेता है। इनको बनाने पर इससे पूरे जिले में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और कठूमर कस्बे में वैश्य समाज एवं कस्बा वासियों ने सुनील बजाज भाजपा मंडल अध्यक्ष कठूमर को भरतपुर सांसद प्रतिनिधि नियुक्त होने पर सांसद रंजीता कोली का आभार व्यक्त किया है एवं खुशी की लहर है।

स्कूली बच्चों के लिए आफत बनी सड़क

मरुधर हिन्द/ हवासिंह चौधरी

बहरोड़। कस्बे के नजदीकी गांव खोहरी, बनाड़ वह उटोली वाले रास्ते पर बरसात के दिनों में पानी भर जाने से आमजन वही स्कूल जाने आने वाले बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस और ना ही तो प्रशासन और ना ही राजनेता कोई ध्यान दे रहे हैं ।जिसके चलते आए दिन स्कूली बच्चे रोड पर भरे हुए पानी में साइकिल के साथ में गिर जाते हैं। बेबस होकर गंदे पानी में भीजे हुए घर वापस लौटना पड़ता है।सरपंच खोहरी सहित अनेक लोगों को भी इसके बारे में बच्चों के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आए दिन बच्चों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए तीन ट्रैक्टर सहित दो गिरफ्तार

मरुधर हिन्द/ रमाकान्त शर्मा

बानसूर - डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि अवैध खनन को लेकर काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी।जिसको लेकर आज खनन विभाग व वन विभाग के साथ मिलकर पुलिस ने हमीरपुर के पहाड़ों में अवैध खनन को लेकर कार्यवाही की गई। जिसमें पुलिस ने पत्थरों से भरे तीन ट्रैक्टर ट्रॉली सहित लक्खीराम पुत्र महावीर निवासी मलूवास, हेमसिंह पुत्र रामकिशन निवासी डोडिया का बास को गिरफ्तार किया है। वही अशोक पुत्र परबत निवासी मुंडली पुलिस को देखकर भागने में कामयाब हो गया। वहीं डीएसपी ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी अवैध खनन हो रहा हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

हरित बानसूर अभियान के तहत होलावास में किया गया वृक्षारोपण

मरुधर हिन्द/रमाकान्त शर्मा

बानसूर के गांव होलावास में सरपंच सतपाल चौधरी के नेतृत्व में बानसूर को हरा-भरा करने के लिए हरित बानसूर अभियान को लेकर वृक्षारोपण किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच सतपाल सिंह जाट ने बताया कि बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की ओर से जारी बानसूर हरित अभियान के तहत आज पंचायत क्षेत्र के कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि आज सभी ग्राम वासियों के साथ मिलकर क्षेत्र में 500 पेड़ लगाकर बानसूर हरित अभियान में भागीदारी निभाई। वही इस अवसर पर सरपंच सतपाल सिंह जाट ,चुन्नीलाल ,सपना, नीरू,सुंदरलाल मीणा, बाबूलाल सेन, रामकुवार मीणा, जितेन्द्र सेन सहित ग्रामीण मौजूद रहें।

दखल

अवैध खनन पर लगाम जरूरी

एनजीटी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात क्षेत्र के 548 वर्ग किलोमीटर में खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। अरावली की हरियाली लौटाने की दृष्टि से न्यायाधिकरण ने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने को कहा था और साथ ही क्षेत्र में कचरा फेंकने पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन सरकार की लापरवाही और खनन माफिया के दबदबे से ये दोनों ही काम नहीं हो पाए और अवैध खनन आज भी जारी है।

देश के ज्यादातर राज्यों में अवैध उत्खनन का धंधा जोरों पर है। इसमें लगे माफिया इतने ताकतवर होते जा रहे हैं कि बड़े अधिकारियों की हत्या करने में तक में नहीं हिचकिचाते। शायद ही कोई ऐसा साल गुजरता हो जब ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन को लोगों पर हमले और उन्हें बेदर्दी से मार डालने की घटनाएं सामने न आती हों। ताजा उदाहरण हरियाणा के नूंह में एक पुलिस उपाधीक्षक की डंपर से कुचल कर की गई हत्या है। कानून के शासन को यह चुनौती अरावली की उन पर्वत शृंखलाओं में मिल रही है, जो हरियाणा राज्य के साथ दिल्ली और इससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आती हैं। लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस अवैध उत्खनन पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत शृंखला को अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है।

शीर्ष न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद पिछले आठ साल में खनन माफिया ने चार सौ मीटर व्यास और साढ़े तीन सौ मीटर ऊंचे 31 पहाड़ों को जमींदोज कर डाला। पहाड़ नूंह के तावडू कस्बे में पंचगांव और चिला गांव में फैले थे। यहां से निकाले गए पत्थर की खपत हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भवन और सड़क निर्माण में होती है। गुरुग्राम को आधुनिक शहर बनाने दस हजार एकड़ प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र को नेस्तनाबूद कर दिया गया। याद किया जाना चाहिए कि अवैध खनन को लेकर दस साल पहले भी मध्यप्रदेश के मुरैना में एक आईपीएस अधिकारी की ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। किसी तरह यह अवैध खनन रुके, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर राजस्थान के भरतपुर में साधु-संतों का एक समूह पिछले डेढ़ साल से आंदोलन कर रहा है। इतने दिनों में भी कोई सुनवाई नहीं होने पर हाल में एक संत ने आत्मदाह तक कर लिया।

ऐसा भी नहीं कि अवैध खनन केवल अरावली की पहाड़ियों में चल रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण से खनन माफिया की जड़े देशभर में गहरी होती जा रही हैं। विडंबना तो यह कि इस पर अंकुश की बजाय ऐसे नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे वैध-अवैध उत्खनन का दायरा बढ़ता रहे। मुश्किल यह है कि प्राकृतिक संपदाओं के अधिकतम दोहन को आधुनिक एवं आर्थिक विकास का नीतिगत आधार बना लिया गया है। लेकिन भारत में यह संकट दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले चुका है। प्राकृतिक संसाधनों का जिस बेरहमी से दोहन जारी है, उस परिप्रेक्ष्य में मौजूदा विकास की निरंतरता तो बनी नहीं रह सकती, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से देंखे तो विकास की यह आवधारणा उस बहुसंख्यक आबादी के लिए जीने का भयावह संकट खड़ा कर सकती है, जिसकी रोजी-रोटी की निर्भरता ही प्रकृति पर अवलंबित है। इसी खतरे को भांपते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में अरावली पर्वत शृंखलाओं से उत्खनन पर प्रतिबंधित लगा दिया था। लेकिन पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से इस पर अमल में लापरवाही बरती जा रही है।

नतीजतन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने एक बार फिर इन सबसे पुरानी पर्वत शृंखलाओं को बचाने के लिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पूरे अरावली क्षेत्र में सड़क निर्माण और पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से यह संदेश गया था कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन नूंह की घटना बता रही है कि अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी रहा। सवाल है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आज सीमेंट, कंक्रीट व लोहे की संरचनाओं से जुड़ा आधुनिक विकास हो अथवा कंप्यूटर व संचार क्रांति से संबंधित प्रौद्योगिक विकास, सबकी निर्भरता प्राकृतिक संपदा पर ही है। इस विकास की बुनियाद जल, जंगल और जमीन पर तो टिकी है ही, खनिज, जीवाश्म ईंधन, रेडियोधर्मी और तरल पदार्थ भी विकास के अपरिहार्य पहलू बन चुके हैं। हालांकि ये खनिज संपदाएं अब अकूत नहीं रहीं। बेशुमार दोहन से इनके भंडार भी तेजी से घट रहे हैं। लिहाजा प्रकृति के समक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन का संकट गहराने के साथ बड़ी आबादी के जीने का अधिकार भी खतरे में पड़ता जा रहा है। क्योंकि प्रकृति के खजाने लूट लिए जाएंगे तो जीने के अधिकार के प्रावधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

एनजीटी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद व मेवात क्षेत्र के 548 वर्ग किमी में खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। अरावली की हरियाली लौटाने की दृष्टि से न्यायाधिकरण ने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने को कहा था और साथ ही क्षेत्र में कचरा फेंकने पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन सरकार की लापरवाही और खनन माफिया के दबदबे से ये दोनों ही काम नहीं हो पाए और अवैध खनन आज भी जारी है। गौरतलब है कि अरावली की पहाड़ियां दुनिया की प्राचीनतम पर्वत शृंखलाओं में से हैं। लगभग आठ सौ किलोमीटर के दायरे में फैली ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हैं। मानव समुदाय के लिए इन पहाड़ियों का कुदरती महत्व है। इनकी ओट ही पश्चिमी रेगिस्तान को फैलने से रोके हुए है, वरना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो उपजाऊ भूमि है, उसे रेगिस्तान में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा।

अवैध खनन सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में भी उत्खनन की जारी रहने से वन क्षेत्रों और नदियों की गहराई पर असर पड़ा है। पश्चिम के ये वन प्रांत दुर्लभ वनस्पतियों और जैव विविधता के अनुपम उदाहरण हैं। यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए भी सर्वोच्च न्यायलय को पहल करनी पड़ी थी। मध्य क्षेत्र में भी प्राकृतिक संपदाओं के बेहताशा दोहन से सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां और कई नदियों का वजूद संकट में है। छत्तीसगढ़ में कच्चे अयस्क के अति दोहन ने शंखिनी नदी को प्रदूषित कर डाला है। मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में लगे इस्पात संयंत्र रोजाना करीब साठ टन दूषित मलवा चंबल और चामला नदियों में बहा कर उन्हें दूषित बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को गड़बड़ाने वाली रेणुका बांध परियोजना को रद्द करने की भी मांग उठ रही है। इस परियोजना को अस्तित्व में लाने का मुख्य मकसद दिल्लीवासियों को अतिरिक्त 27 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन मुहैया कराना है।

वर्ष 1994 की इस परियोजना पर पांच सहयोगी प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तर प्रदेश समझौता करने एकजुट हुए थे। लेकिन राजस्थान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में पारियोजना रद्द मानी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। विषेशज्ञों का मानना है कि यह परियोजना जारी रहती है तो निचले हिमालय क्षेत्र में दो हजार हेक्टेयर में फैले जंगल और कृषि क्षेत्र डूब जाएंगे। संकट इसलिए गहराता जा रहा है कि हम विकास का ऐसा आदर्श और संतुलित रूप तैयार करने में नाकाम रहे हैं जिसमें विकास की गतिशीलता भी बनी रहे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी धक्का न पहुंचे। आधुनिक विकास का आधार प्राकृतिक संसाधन हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे नीतिगत उपाय करती हैं, जिससे हर प्रकार के निर्माण कार्यों में कोई अड़चन न आए। खासतौर से भवन और सड़कों के निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल खनन साम्रगी का होता है। इस्पात की भी इसमें बड़ी खपत होती है।

प्रमोद भार्गव
(वरिष्ठ पत्रकार)

राज-विचार

पीओके पर पाक को कड़ा संदेश

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर कहा कि यह हिस्सा भारत का है और रहेगा। कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आक्रामकता सही दिशा में है। जब तक भारत इस मुद्दे पर पूरी दुनिया में पाक को नहीं घेरेगा, तब तक वह सुधरने वाला नहीं है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर जम्मू से हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है कि गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। पूरा देश इस तथ्य पर एकमत है, संसद में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, बावजूद उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। सिंह ने आगे कहा कि भगवान शिव का हिमस्वरूप हमारे पास है और मां शारदा पीठ आज भी नियंत्रण रेखा के उस पार हैं, ऐसा क्यों है? राजनाथ ने विशवास दिलाया कि आज नहीं तो कल हमारी यह मन्नत भी पूरी होगी। कश्मीर के मुद्दे पर रक्षामंत्री ने जिस तरह का रुख दिखाया है, वैसी आक्रामकता जरूरी है, क्योंकि पाक जब-तब वैश्विक मंचों पर कश्मीर कार्ड खेलने में लगा है। इसलिए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। भारत ने गुलाम कश्मीर पर अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को कई मर्तबा इसे खाली करने की चेतावनी दी है। किंतु उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती।

मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर साबित किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर न केवल भारत का है, बल्कि वहां के लोग गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में भी आ रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में पाक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं। इसकी वजह वहां रह रहे नागरिकों का शोषण और दमन है। इस दमन की तस्वीरें वीडियो से सामने आती रही हैं। पीओके, गिलगित-बाल्टिस्तान और ब्लूचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब एवं लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है, वहीं ब्लूचिस्तान की भूमि से खनिज तथा तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए हैं। नतीजतन यहां खेती-किसानी, उद्योग-धंधे, शिक्षा-रोजगार और स्वास्थ्य-सुविधाएं तथा पर्यटन सब चौपट है।

दरअसल कशमीर की समस्या आज की देन नहीं हैं। 1948 में कांग्रेस और नेशनल क्रांफ्रेंस की कारगुजारियों के चलते यहां बदहाली आज तक कायम है। कश्मीर के ये हालात इसलिए भी उत्पन्न हुए, क्योंकि यहां शुरुआत में लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं अपनाया गया। शेख अब्दुल्ला को राज्य का बड़ा नेता होने के कारण सीधे प्रधानमंत्री बना दिया गया। यदि स्थानीय नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए राज्य का प्रधानमंत्री चुनने का मौका दिया होता तो लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा पुख्ता होता। हालांकि अब धारा-370 एवं 35-ए हटने के बाद कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं, इसी का परिणाम है कि इस बार घाटी में सात लाख से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं, जो जनता की आर्थिक बहाली का कारण बन रहे हैं। कश्मीर में दिन-प्रतिदिन जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं, उससे लगता है कि हमें पीआके जल्द मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीओके में रहने वाले लोग पाक के खिलाफ मोर्चा बुलंद करेंगे।

विचाराधीन कैदी और लोकतंत्र

भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में पड़े विचाराधीन कैदियों की ओर देश का ध्यान खींचा है तथा एक ऐसे मुद्दे को सामने रखा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है, नागरिकों की आजादी छिनती है और अधिकतर जांचों में जमानत देने की जगह जेल भेजना कायदा बनता जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने एक संबोधन में रेखांकित किया कि हमारे देश में जेलों में बंद 6.10 लाख नागरिकों में 80 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में प्रक्रिया ही दंड बन गई है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों से लेकर जमानत मिलने में मुश्किलों तक की इस प्रक्रिया में लंबे समय तक जेलों में बंद लोगों के इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कैदी ब्लैक बॉक्स की तरह हैं। वे ऐसे नागरिक हैं, जिन्हें अनदेखा और अनसुना कर दिया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे मुद्दे को उठाया है, जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह कोई हाल में आई अस्थायी गिरावट नहीं है, बल्कि भारतीय व्यवस्था की स्थायी विशेषता बन चुकी है।

यह पहली बार नहीं है कि जेलों में बंद आरोपियों के प्रति चिंता व्यक्त की गई हो। 2010 में राष्ट्रीय विधिक अभियान के तहत भी विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने का बीड़ा उठाया गया था। पर धरातल पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सजा दिलाने लंबी जांच की बजाय तुरंत हिरासत में लेने के रवैये से भी न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है क्योंकि जमानत की अर्जियों की तादाद बहुत अधिक है।

सजा दिलाने लंबी जांच की बजाय तुरंत हिरासत में लेने के रवैये से भी न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है क्योंकि जमानत की अर्जियों की तादाद बहुत अधिक है। चूंकि हिरासत में लेना आम बात है, तो अग्रिम जमानत के लिए भी बहुत सारे लोग अदालत पहुंचते हैं। इनसे बड़ी अदालतों में बोझ बढ़ता जाता है। इन सबसे ऐसी व्यवस्थागत समस्या पैदा हो गई है, जिसका समाधान जजों की संख्या बढ़ाकर नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारे यहां अभियुक्तों को सजा देने की दर बहुत ही कम है। ऐसे में ठोस जांच दरकिनार कर दी जाती है और मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखना ही सजा बना दिया जाता है। इससे न्याय व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत, जिसमें दोष सिद्ध होने तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है, ही खारिज हो जाता है।

इस माह की 11 तारीख को अपने 85 पन्ने के आदेश में न्यायाधीश एसके कौल व एमएम सुंदेश ने समस्या के व्यवस्थागत प्रकृति की ओर संकेत किया है-अदालतें सोचती हैं कि चूंकि सजा होने की संभावना बहुत ही कम है, तो जमानत की अर्जियों पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हम जमानत पर विचार करते हुए बहुत सी बातों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसका दंड से लेना-देना नहीं है। अगर कोई लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बरी हो जाता है, तो वह बेहद गंभीर अन्याय है। कामकाज का कोई लेना-देना राजनीति या नेताओं या एजेंडे से नहीं होता। व्यवस्था का हर जगह होना उसका संत्रास है। वह हवा व पानी में घुल-मिल जाता है तथा बहुत से लोगों को जेल में डालकर उनमें से कुछ सबसे कमजोर नागरिकों को भूल जाता है। इससे कैसे व्यवस्था की रीढ़ टूटती है, हम उसे आसानी से या ठीक से नहीं समझते।

एक तो यह बिना मुकदमे के सजा दे देता है, जिसके लिए सबूतों का संज्ञान लिया जाना चाहिए और हर तरह से परखने के बाद ही अभियुक्त को दोषी ठहराना चाहिए। राज्य ने एकदम बुनियादी स्तर पर और रोजमर्रा के काम में ऐसा कर न्यायिक व्यवस्था को खत्म भले न किया हो, पर उसे अप्रासंगिक जरूर कर दिया है। यह सब न्यायपालिका के सहयोग से ही हुआ है, जहां लगातार हिरासत में रखने के फैसले दिये जाते हैं और जमानत पाना मुश्किल होता है क्योंकि मामले के बारे में अक्सर न तो ठीक से विचार किया जाता है और कई बार तो उसके बारे में पूछा भी नहीं जाता। अगर हिरासत में रखने की अनुमति चलन बन जाए, तो पुलिस जजों को लेकर निश्चिंत हो जाती है और इसका सीधा व तुरंत असर जांच की गुणवत्ता पर पड़ता है। न्यायाधीश कौल और सुंदेश ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में दिए गए एक निर्णय को उद्धृत करते हुए लिखा कि हमारे इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिसकर्मी अभियुक्त को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं करें और मजिस्ट्रेट लापरवाही से एवं यांत्रिक तौर से उसे पुलिस हिरासत में रखने का आदेश न पारित करें। वे आगे लिखते हैं, हिरासत में रखने का आदेश देने का अधिकार गंभीर दायित्व है। इससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है तथा इस अधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

हमारा अनुभव हमें बताता है कि इस अधिकार का प्रयोग उस गंभीरता से नहीं किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में हिरासत में रखने का आदेश नियमित, लापरवाही भरा और बिना सोचे दिया जाता है। असल में, हिरासत का आदेश इतना सामान्य हो गया है कि पुलिस अधिकारी समुचित या पूरा विवरण भी पेश करने की जहमत नहीं उठाते। कभी-कभी इससे जांच एजेंसियों में घमंड भी भर जाता है कि कुछ भी चल सकता है। इससे जांच के शुरुआती चरण में ही मामला भटक जाता है, जबकि इस अहम मोड़ पर बहुत सावधानी बरतने और समयबद्ध होकर काम करने की जरूरत होती है। ऐसा होने से हिरासत में होने वाली हिंसा के मामले से भी पुलिस का बचाव हो जाता है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद यह समस्या भी गंभीर होती जा रही है।

इसलिए यह कोई अचानक नहीं हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से जमानत पर एक कानून बनाने को कहा है। न्यायाधीश कौल और सुंदेश ने रेखांकित किया है, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में बने कानूनों की तरह जमानत देने के बारे में विशेष कानून लाने पर विचार करे। निश्चित ही उल्लेखनीय पहल होगी। वैधानिक व्यवस्था में विशेष दिशा-निर्देशों को रखा जा सकता है, लेकिन बड़ी समस्या औपनिवेशिक मानसिकता की है, जो अभी भी भारतीय नौकरशाही पर हावी है। इसके साथ ही अच्छा करने वाले लोगों के सहयोग के लिए निवेश की कमी तथा व्यवस्था के साथ हेर-फेर करने वालों को सजा देने का अभाव जैसी समस्याएं भी हैं। यहां पर अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए। शुरू से ही मामलों की निगरानी होनी चाहिए और जांच एजेंसियों की मांग की समीक्षा होनी चाहिए।

ऐसा करने से हमारी जांच व्यवस्था की कई खामियां दूर हो सकेंगी और एजेंसियां अधिक उत्तरदायी होंगी। साथ ही, इससे पुलिस सतर्क रहेगी और जेलों में भीड़ कम होगी तथा पूरी व्यवस्था के प्रभाव में बेहतर होगी। उच्चतम न्यायालय ने साल 2014 में व्यवस्था दी थी कि उन विचाराधीन आरोपियों को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए जिन्होंने अपने ऊपर लगे अभियोग की संभावित अधिकतम सजा का आधा समय बतौर आरोपी जेल में व्यतीत कर लिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र में प्रत्येक कारावास पर जाकर इस प्रकार के कैदियों की रिहाई के लिए आवश्यक प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इन आदेशों के बाद लंबी अवधि से जेलों में बंद विचाराधीन कैदी रिहा हो सकेंगे।

जगदीश रत्नानी
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

अब भारत कमजोर देश नहीं बल्कि शक्तिशाली राष्ट्र है। उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करने का कोई साहस नहीं दिखा सकता। यदि युद्ध हुआ तो भारत की जीत होगी।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

आतंकवाद शांति और विकास के साझा लक्ष्य का बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान आतंकवाद को पीओके में पाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बुराई के खिलाफ एकजुट हो।

एस जयशंकर, विदेश मंत्री

सत्यार्थ

विश्वास होना जरूरी

राजा ययाति और देवयानी पति-पत्नी थे। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। जब इनका विवाह हुआ था दैत्यों की राजकुमारी शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ दासी के रूप में गई थी। दरअसल शर्मिष्ठा देवयानी से एक शर्त हार गई थी और इस कारण उसे देवयानी की दासी बनना पड़ा था। उस समय शुक्राचार्य ने ययाति से एक वचन लिया था कि वह कभी भी देवयानी के अलावा किसी अन्य स्त्री से रिश्ता नहीं रखेगा। ययाति ने भी शुक्राचार्य को ये वचन दे दिया था। कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती हो गई। दूसरी ओर शर्मिष्ठा एक दासी के रूप में ययाति के महल के पीछे छोटी सी कुटिया में रह रही थी। एक दिन ययाति शर्मिष्ठा को देखकर उसकी ओर मोहित हो गए और उन्होंने शर्मिष्ठा से संबंध बना लिए। राजा ययाति शुक्राचार्य को दिया हुआ वचन भी भूल गए थे। बाद में शर्मिष्ठा और ययाति की बात जब देवयानी को मालूम हुई तो वह अपने पिता के घर पहुंच गई और पूरी बात बता दी। शुक्राचार्य इस बात से बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने ययाति को शाप दे दिया कि वे तुरंत बूढ़े हो जाएंगे। शाप के असर से ययाति बूढ़े हो गए। इस तरह देवयानी और ययाति का वैवाहिक रिश्ता बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। इस कथा की सीख यही है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखें, साथ ही कभी भी एक-दूसरे का भरोसा न तोड़ें। वैवाहिक जीवन में भरोसा टूटता है तो रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल के साथ ही विश्वास न हो तो रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। श्रीमद्भागवत ग्रंथ में राजा ययाति और देवयानी की कथा से ये बात समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पति या पत्नी दोनों एक-दूसरे से कुछ न छिपाएं। अगर ऐसा होगा तो जीवन में तनाव बढ़ेगा।

मुकेश कुमार

प्रीत सिंह स्टारर पैन इंडिया सिंगल 'माशूका' रिलीज

जेजस्ट म्यूजिक ने इंडिया का पहला पैन इंडिया सिंगल 'माशूका' रिलीज कर दिया है। ये गाना हिंदी, तेलुगु और तमिल में जारी हुआ है। गाने में खूबसूरत रकुल प्रीत सिंह को पॉप क्वीन गॉडेस के रूप में पेश किया हैं, जो हमें अपने लेंस के जरिए अपनी विविड, खूबसूरत और बब्ली पॉप वर्ल्ड में ले जाती हैं। रकुल प्रीत सिंह देखने में एक दृष्टि की तरह दिखती हैं, उनकी आभा बहुत शक्तिशाली है और पूरे म्यूजिक वीडियो में उनकी एनर्जी देखने लायक हैं। 'माशूका' का म्यूजिक वीडियो एक बहुत ही अलग पॉप दुनिया का वादा करता है। सेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए रंग वाइब्रेंट हैं, जो वीडियो को ऐजी बनाता है। 'माशूका' सबसे बोल्ड और अलग गाना है जो बी-टाउन गर्ल-नेक्स्ट-डोर रकुल प्रीत सिंह को एक पॉप-क्वीन में बदल देता है। म्यूजिक वीडियो कई रचनात्मक दिमागों का नतीजा है जैसे कि निर्देशक चरित देसाई, डी.ओ.पी, आदिल अफसर, और ऑर्ट डायरेक्टर मधुसूदन एन। इस म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करते हुए, निर्माताओं का कहना हैं, 'हम आभारी हैं कि हमने अपने लेटेस्ट वेंचर के लिए रकुल प्रीत सिंह के साथ हाथ मिलाया। उनकी एनर्जी बेजोड़ है। हमारा गोल एक अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाना है और असीस कौर, आदित्य अयंगर और देवांश शर्मा जैसे प्रतिभाशाली गायकों की मदद से हम इसे हासिल करने में सक्षम थे। रकुल एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री और एक असाधारण कलाकार हैं। उन्होंने म्यूजिक वीडियो में इंप्रेसिव काम किया है।' वहीं रकुल प्रीत सिंह कहती हैं, 'माशूका की शूटिंग मेरे लिए एक अनुकरणीय अनुभव रहा है। शूटिंग के लिए निर्माताओं के पास सबसे शानदार आइडियाज में से एक था। यह गाना न सिर्फ पार्टी एंथम है बल्कि यह वीडियो अपनी तरह का अनोखा है। वीडियो बोल्ड, मजेदार और सेक्सी है। इसमें वे सभी चीजें है जो एक बेहतरीन म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए जरूर होती हैं।' इस गाने को असीस कौर, आदित्य अयंगर और देवांश शर्मा ने गाया हैं।

धनुष बोले- साउथ का नहीं, हमें केवल इंडियन एक्टर कहा जाए

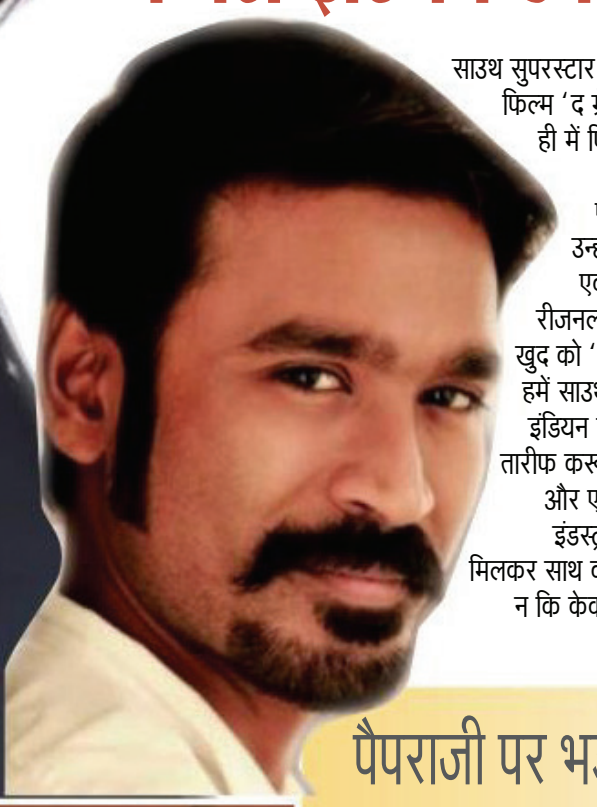

साउथ सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रे मैन' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें एक 'साउथ एक्टर' के तौर पर पहचान मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक बड़ी इंडस्ट्री बनाएं और साउथ, नॉर्थ या रीजनल के बजाए नेशनल फिल्में बनाएं। धनुष ने खुद को 'साउथ एक्टर' कहे जाने पर कहा, 'अगर हमें साउथ या नॉर्थ एक्टर कहने के बजाए सब हमें इंडियन एक्टर कहकर बुलाएंगे तो मैं इस बात की तारीफ करूंगा। यह समय है कि हम सभी साथ आएं और एक बड़ी इंडस्ट्री बनाएं। यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यह बहुत अच्छा होगा अगर हम सब मिलकर साथ काम करें और सभी के लिए फिल्में बनाएं, न कि केवल साउथ, नॉर्थ या रीजनल इंडस्ट्री बल्कि नेशनल फिल्में बनें।'

पैपराजी पर भड़क गए अर्जुन कपूर

अर्जुन कपूर जल्द ही फिल्म एक विलेन रिटर्न्स में नजर आने वाले हैं। इन दिनों वह अपनी इस फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अर्जुन पैपराजी पर गुस्सा होते हुए नजर आए। दरअसल, ये वीडियो मुंबई के एक रोड का है, जहां पर उनका एक फैन फोटो क्लिक करवाने के लिए आता है। वहीं पैपराजी अर्जुन की फोटो क्लिक करने के लिए रोड को घेर लेते हैं। इस पर एक्टर उन सभी पर भड़क जाते हैं और कहते है, 'अंदर आओ पहले तो आप लोग, हमारी रोड नहीं है, आप लोग ये करते हो नाम हमारा खराब होता है'। अर्जुन के इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रह हैं।

राजश्री की फिल्म 'ऊंचाई' में नजर आयेंगे अमिताभ सहित ये दिग्गज

राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म 'ऊंचाई' 11 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। इसकी घोषणा राजश्री प्रोडक्शन हाउस ने अपने सोशल मीडिया पर कर दी है। राजश्री प्रोडक्शन की ये 60वीं फिल्म सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी है। इस फिल्म से निर्देशक सूरज बड़जात्या 7 सालों बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्म थी 'प्रेम रतन धन पायो' जिसमें सलमान खान और सोनम कपूर ने काम किया था। अपने शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'सौदागर'(1973) में काम कर चुके हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता, सारिका, नफीसा अली सोढ़ी, डैनी डेन्जोंप्पा और परिणीति चोपड़ा आदि हैं। राजश्री प्रोडक्शन के कमल कुमार बड़जात्या, स्व राजकुमार कुमार बड़जात्या और अजित कुमार बड़जात्या ने महावीर जैन (महावीर जैन फिल्मस) और नताशा मलपानी ओसवाल (बॉण्डलेस मीडिया) के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को साकार किया है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दिल्ली, आगरा, मुम्बई, लखनऊ, नेपाल और कानपुर में हुई है।

लाल सिंह चड्ढा के 'तुर कलेयां' गाने का वीडियो हुआ रिलीज

लाल सिंह चड्ढा सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है और मेकर्स एक एक कर फिल्म से जुड़ी सभी पहेलियों का खुलासा कर रहें है। अब निर्माताओं ने 'तुर कलैयां' गाने का एक नया म्यूजिक वीडियो जारी किया है और बिना किसी संदेह के, यह अब तक के सबसे अच्छी तरह से शूट किए गए वीडियोज में से एक है।

'तुर कलेयां' गाना न केवल फिल्म के सबसे खूबसूरत सीक्वेंस में से एक है, बल्कि लाल सिंह चड्ढा की ट्रांसफॉर्मेशन्ल जर्नी पर भी रोशनी डालता है, जो आखिरकार जीवन में सभी बाधाओं के बावजूद खुद से प्यार करना सीख जाता है। अरिजीत सिंह, शादाब फरीदी, और अल्तमश फरीदी द्वारा गाया गया, प्रीतम द्वारा रचित हैं वहीं गाने की लीरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के हैं। इस मोटिवेशनल सॉग को देश भर में प्यार और सराहना मिली है। 'तुर कलेयां' ' फिल्म का सबसे लंबा शॉट सीक्वेंस है और आमिर खान, जो फिल्म में लाल सिंह चड्ढा की भूमिका निभा रहे हैं, ने म्यूजिक वीडियो को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस गाने में निर्माताओं ने देश और इसकी संस्कृति की अनकही कहानियों को बताने वाले हर अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को कवर करके भारत और उसके लोगों की सुंदरता को कैप्चर किया है।

बता दें, आमिर खान ने 'तुर कलेयां' के लिए म्यूजिक वीडियो की शूटिंग से अपने दर्द भरे घुटनों के साथ की थी और बावजूद इसके उन्होंने गाने में अपना बेस्ट शॉट दिया हैं। वास्तव में, निर्माताओं ने विशिष्ट शॉट्स प्राप्त करने के लिए महीनों तक भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की, जो केवल कुछ सेकंड के लिए वीडियो में हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस, किरण राव और वायकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित 'लाल सिंह चड्ढा' में करीना कपूर खान, मोना सिंह और चैतन्य अक्किनेनी भी हैं। ये फिल्म फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक है। लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है।

सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे मिथुन चक्रवर्ती

मिथुन चक्रवर्ती लंबे वक्त से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी वह काफी एक्टिव हैं। मिथुन चक्रवर्ती यूं तो आज भी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अपने फैंस के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन तमाम बातें ऐसी हैं जो उनके फैंस को शायद ही कभी पता चल पाती हैं। एक्टर ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपने सबसे खराब वक्त को लेकर बातचीत की और बताया कि तब वह सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, 'मैं आमतौर पर इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, और किसी खास फेज के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। स्ट्रगल के उन दिनों के बारे में बात नहीं ही करें तो ठीक है, क्योंकि ये नए कलाकारों को डिमोटिवेट करता है। हर कोई स्ट्रगल्स से गुजरता है लेकिन मेरा वाला कुछ ज्यादा ही मुश्किल था।' मिथुन चक्रवर्ती ने बताया, 'कई बार मैं सोचा करता था कि मैं कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं सुसाइड करने के बारे में सोचने लगा था। यहां तक कि मैं कई कारणों से कोलकाता से वापस भी नहीं आ सका। लेकिन मेरी सलाह यही है कि कभी भी बिना लड़े अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।'

हाथों में हाथ डाले घूमते नजर आए ऋतिक रोशन-सबा आजाद

इन दिनों ऋतिक रोशन और सबा आजाद अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। आए दिन दोनों को साथ स्पॉट किया जाता है। अक्सर सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं। हाल ही में सबा और ऋतिक विदेश से छुट्टियां मनाकर लौटे हैं। एक बार फिर हाथों में हाथ डाले इन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों स्टार्स के बीच की नजदीकियां देख इनके फैंस बेहद खुश हैं, लेकिन वहीं कुछ नेटिजन्स ने इनकी एज-शेमिंग कर दी। दोनों के बीच के उम्र के अंतर पर यूजर्स ने कमेंट किए हैं। बता दें कि दोनों की उम्र में करीब 12 साल का फासला है। सबा की उम्र जहां 36 वर्ष है, वहीं ऋतिक रोशन की उम्र 48 साल है। इस बात पर अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स इन पर कमेंट करते रहते हैं। हाल ही में जब इन दोनों को एयरपोर्ट पर देखा गया। इसका वीडियो एक सेलिब्रिटी पैपराजी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। जिस पर एक यूजर ने लिखा, 'मुझे लगा कि यह इनकी बेटी है।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बाप बेटी'। एक यूजर ने तो इन्हें नशे में ही बता दिया। यूजर ने कमेंट किया, 'नशे में तो हो दोनों, तभी न...'

पाक जेलों में 4 महिला समेत 682 भारतीय नागरिक बंद: मुरलीधरन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पाकिस्तान की जेलों में 4 महिलाओं समेत कुल 682 भारतीय नागरिक बंद हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि इनमें 17 ऐसे हैं, जो 10 सालों से अधिक समय से पड़ोसी देश की हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 2,214 भारतीयों को पाकिस्तान से स्वदेश ला चुका है। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा द्वारा पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीयों नागरिकों की संख्या पूछे जाने पर मुरलीधरन ने कहा कि कॉन्सुलर एक्सेस संबंधी भारत-पाकिस्तान करार के अंतर्गत एक जुलाई 2022 को पाकिस्तान द्वारा दी गई कैदियों की सूची के अनुसार पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि उसकी जेलों में 633 मछुआरे और 49 नागरिक कैद हैं, जो भारतीय हैं। उन्होंने कहा इन 682 कैदियों में से 4 महिलाएं हैं और 17 कैदी 10 वर्ष से भी अधिक समय से पाकिस्तान की हिरासत में है। विदेश राज्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ राजनीतिक चैनलों के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को उठा कर रही है और सजा पूरी कर चुके सभी भारतीय कैदियों की रिहाई एवं स्वदेश वापसी की मांग करती रही है। मुरलीधरन ने कहा कि सरकार, पाकिस्तान में भारतीयों कैदी के कल्याण, सलामती और सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है।

मिशन 2024 में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, दिल्ली में अखिलेश यादव से की मुलाकात

नई दिल्ली। 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर हम सभी राजनीतिक दलों ने अपने समीकरणों को धार देने की शुरुआत कर दी है। वर्तमान में देखें तो जहां ममता बनर्जी एक अलग गठबंधन की कवायद कर रही हैं। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री नई दिल्ली पहुंचे हैं जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया है कि दोनों नेताओं के बीच वर्तमान के राजनीतिक हालात और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। हाल के दिनों में देखें तो अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की यह दूसरी मुलाकात थी। यही कारण है कि अपने सियासी गठबंधन के कयास शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्ष के नेता भी हैं। दिल्ली की राजनीति को साधने के लिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि के चंद्रशेखर राव लगातार अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिए मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी 48 इमारतों पर कार्रवाई के आदेश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि एयरपोर्ट और रनवे के बीच में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना करें और ऐसी इमारतों पर जरूरी कार्रवाई की जाए. अदालत ने आदेश दिया है कि जिस इमारत की ऊंचाई ज्यादा है, उसे कम किया जाए. इससे पूर्व बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि विमानन में, सब कुछ हवाई यातायात नियंत्रण पर निर्भर करता है और एक गलती से कुछ भी हो सकता है. अदालत मुंबई हवाई अड्डे के पास ऊंची इमारतों से विमानों के लिए खतरों पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही थी. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम.एस.कार्णिक की खंडपीठ अधिवक्ता यशवंत शेनॉय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुंबई शहर के हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निर्धारित ऊंचाई सीमा से ऊपर के भवनों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. शेनॉय ने तर्क दिया कि इन इमारतों से विमान के यहां हवाईअड्डे पर उड़ान भरने और उतरने के समय खतरा हो सकता है और किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है. हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगरपालिका से इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई की है, इस पर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है. यह देखते हुए कि इस मुद्दे ने सभी को चिंतित किया, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अजय देवगन-स्टारर हिंदी फिल्म 'रनवे 34' देखी. कुछ भी पायलट पर निर्भर नहीं करता है. सब कुछ हवाई यातायात नियंत्रण पर निर्भर करता है.' 'हमें लगता है कि पायलट ने घोषणा की है कि हम लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए तैयार हैं और बाहर का तापमान ऐसा ही है और सब कुछ ठीक है. लेकिन यह सब कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है. इधर-उधर एक गलती...कुछ भी हो सकता है.'

कहीं पर भी बाल विवाह हुआ तो इलाके के मुखिया होंगे जिम्मेदार: बिहार सरकार

पटना। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को राज्य में बाल विवाह निषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी इलाके से अवैध विवाह की सूचना मिलती है तो संबंधित मुखिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र से बाल विवाह की सूचना मिलती है तो सरकार संबंधित मुखिया और पंचायत के वार्ड सदस्यों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू करेगी। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ग्राम पंचायतों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने और राज्य में बाल विवाह को रोकने में उनकी भूमिका के बारे में मुखिया को भी जानकारी देने को कहा है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 'बाल विवाह निषेध अधिनियम और दहेज विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी मुखिया को इसे रोकने में अपनी भूमिका को जानना चाहिए क्योंकि वे स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।'' उन्होंने कहा कि आम तौर पर मुखिया गांवों में विवाह प्रमाणपत्र जारी करते हैं इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की जांच करें। मंत्री ने कहा कि यदि बाल विवाह किसी विशेष क्षेत्र में हो रहा है तो संबंधित मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। यदि पंचायती राज विभाग को किसी विशेष इलाके में इस तरह के विवाह के बारे में पता चलता है तो इसके लिए मुखिया को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे में मुखिया अपनी सदस्यता खो देंगे।

अब 18 साल का होने से पहले ही दर्ज करा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम, ईसी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए अब 17 साल से अधिक उम्र के युवा अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक, किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीक-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में सुविधा हो। बयान में कहा गया है, ''अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे।'' निर्वाचन आयोग ने बाद में कहा, ''अग्रिम आवेदन नौ नवंबर, 2022 को या उसके बाद जमा किये जा सकते है, यह वह तारीख है जब मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।''

जलवायु वि के मुद्दों पर विकसित देशों को दावों की भारत ने खोली पोलः सरकार

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत जलवायु संबंधी वित्त के मुद्दों को उठाने में अग्रणी रहा है कि उसके प्रयासों के चलते ही विकसित देशों के उन अतिशयोक्तिपूर्ण दावों की पोल खुली है, जिनमें कहा गया था कि वे विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर संयुक्त रूप से जुटाने को प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2009 में कोपनहेगन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी-15) में विकसित देशों ने विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अमेरिकी अमेरिकी डॉलर संयुक्त रूप से जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विकसित देशों के विफल रहने के कारण पेरिस में आयोजित सीओपी-21 बैठक में 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष लक्ष्य का विस्तार वर्ष 2025 तक करने का निर्णय लिया गया था।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, ''भारत जलवायु संबंधी वित्त के मुद्दों को उठाने में अग्रणी रहा है। भारत के प्रयासों ने बार-बार विकसित देशों की एजेंसियों के दावों को गलत साबित किया है कि यह लक्ष्य पूरा होने के करीब है। साथ ही यह बताया है कि वर्तमान में जुटाया गया जलवायु संबंधी वित्त वास्तव में बहुत कम है।'' उन्होंने बताया कि भारत जलवायु संबंधी नीति की परिमें स्पष्टता लाने और ऐसे वित्त के पैमाने, दायरे और आपूर्ति की गति के महत्व को स्पष्ट करने की मांग करने में भी अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा इस बात पर कायम रहा है कि जलवायु संबंधी वित्त नया और अतिरिक्त (विदेशी विकास सहायता के संबंध में) मुख्य रूप से अनुदान के रूप में होना चाहिए, ऋण के रूप में नहीं। साथ ही यह शमन और अनुकूलन के बीच संतुलित होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जलवायु संबंधी वित्त की परिके संबंध में तथा आकलनों एवं की गई प्रगति के संबंध में अनेक मुद्दे हैं और धन जुटाने के लक्ष्यों को किस हद तक हासिल किया जा सकता है, इसकेअलग-अलग अनुमान हैं। यूएनएफसीसीसी की वित्त संबंधी स्थाई समिति के चौथे द्विवार्षिक आकलन में वर्ष 2018 तक जलवायु संबंधी वित्त प्रवाह के संबंध में एक अद्यतन समीक्षा और इसके रुझान प्रस्तुत किए हैं और इसके मुताबिक कुल सार्वजनिक वित्तीय सहायता वर्ष 2017 में 45.4 अरब तथा वर्ष 2018 में 51.8 अरब डॉलर थी।

अगले सप्ताह दिल्ली आ रही हैं ममता बनर्जी, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अगले सप्ताह दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक उनका चार दिवसीय दिल्ली दौरा 4 अगस्त से शुरू होगा। ममता बनर्जी 8 अगस्त तक दिल्ली में रह सकती हैं। हालांकि, अभी तक तारीखों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। खबर तो यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ममता बनर्जी की मुलाकात हो सकती है। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात 5 या 6 तारीख को संभव है। ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक 55 करोड से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही यह बैठक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अहम हो जाती है। ममता बनर्जी की पार्टी ने फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने एक बार ऐलान किया था कि वह हर संसद सत्र के दौरान दिल्ली आएंगी। इस लिहाज से भी ममता बनर्जी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का मनोबल बढ़ेगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में संसद से कई सदस्यों को निर्लंबित किया गया है जिनमें तृणमूल कांग्रेस के साथ सांसद भी शामिल हैं।

पिता की मौत हो गयी है तो बच्चे का सरनेम बदल सकती है माँः सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

पिता के निधन के बाद बच्चे की नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते मां के पास उपनाम पर निर्णय लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए की। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में महिला को निर्देश दिया था कि वह दस्तावेजों में अपने दूसरे पति का नाम सौतेले पिता के रूप में दर्ज करे। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि दस्तावेजों में महिला के दूसरे पति का नाम 'सौतेले पिता' के रूप में शामिल करने का उच्च न्यायालय का निर्देश 'लगभग क्रूर' और इस तथ्य के प्रति नासमझी को दिखाता है कि यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को कैसे प्रभावित करेगा।

न्यायालय ने कहा कि बच्चे की एकमात्र नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते मां को बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार है और उसे बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ने का भी अधिकार है। शीर्ष अदालत पहले पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां और बच्चे के मृत जैविक पिता के माता-पिता के बीच बच्चे के उपनाम से जुड़े एक मामले से सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा कि अपने पहले पति की मृत्यु के बाद बच्चे की एकमात्र नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते मां को अपने नये परिवार में बच्चे को शामिल करने और उपनाम तय करने से कानूनी रूप से कैसे रोका जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बच्चा इससे अपनी पहचान प्राप्त करता है और उसके नाम और परिवार के नाम में अंतर गोद लेने के तथ्य की निरंतर याद दिलाने के रूप में कार्य करेगा। ऐसे में बच्चे को अनावश्यक सवालों का सामना करना पड़ेगा, जो उसके माता-पिता के बीच एक सहज और प्राकृतिक संबंध में बाधा उत्पन्न करेंगे।

स्कूली शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अच्छा मनुष्य, देशभक्त, रोजगार योग्य बनाना: केजरीवाल

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी स्कूली शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अच्छा मनुष्य, देशभक्त और रोजगार हासिल करने योग्य बनाना है। 'हैप्पीनेस' पाठ्यक्रम के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि जब वह सत्ता में आए थे, तब स्कूलों की स्थिति खराब थी और बोर्ड की परीक्षा के परिणाम भी अच्छे नहीं आते थे। उन्होंने कहा, '' लेकिन अब हम अच्छा कर रहे हैं। हमने विभिन्न पाठ्यक्रम जारी किए हैं और शैक्षणिक दबाव को कम किया है।

'हैप्पीनेस' कक्षाओं से बच्चों का तनाव कम हुआ और इसलिए दिल्ली में छात्रों की आत्महत्या का कोई मामला भी नहीं सामने आया।'' मुख्यमंत्री ने बताया कि वे छात्रों को ऐसा बनाना चाहते हैं, जो ''नफरत'' नहीं बल्कि देश में ''प्रेम के संदेश'' का प्रचार करें। केजरीवाल ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने भी दिल्ली सरकार की 'हैप्पीनेस' कक्षाओं में हिस्सा लिया था और वह उससे काफी प्रभावित भी हुई थीं।

नवनीत राणा की जान को खतरा! शुभचिंतक ने खत लिखकर किया आगाह- सावधान रहें, कुछ लोग पीछा कर रहे

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कुछ महीने पहले मीडिया की सुर्खियों में रही अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल, नवनीत राणा ने हाल के दिनों में हिंदू हित की आवाज बढ़-चढ़कर उठाई है। यही कारण है कि वह कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इन सबके बीच नवनीत राणा को एक गुमनाम खत मिला है। खत में नवनीत राणा को सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसमें यह भी लिखा है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए से संभल कर रहे। आपको बता दें कि नवनीत राणा अमरावती के मेडिकल स्टोर के मालिक उमेश कोल्हे की हत्या का मुद्दा भी खूब उठाया था।

जानकारी के मुताबिक इस पत्र में यह भी लिखा है कि कुछ लोग नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के घर की रेकी की है। राजस्थान बॉर्डर से अमरावती आए थे। हालांकि इस चिट्ठी में किसी का नाम नहीं लिखा है। लेकिन नवनीत राणा को आगाह रहने की बात जरूर की है। फिलहाल नवनीत राणा इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस की ओर से कोई बयान तक नहीं आया है। लेकिन नवनीत राणा की सुरक्षा में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से कट्टरपंथियों ने उमेश कोल्हे की हत्या कर दी थी। नवनीत राणा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।

हाईकोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए जहरीली शराब कांड जांचः कांग्रेस

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

गुजरात में जहरीली शराब पीने से कुछ दिन पहले कई लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने मांग की है कि इस घटना की जांच हाईकोर्ट के किसी जज से कराई जानी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि गुजरात में भाजपा सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि तथाकथित शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब पीने की वजह से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुसार यह जानकारी सामने आई है कि बोटाद जिले में 600 लीटर 'मिथाइल अल्कोहल% (मेथेनॉल) अहमदाबाद से लाया गया था। उसके बाद इसमें पानी मिलाकर जिले के विभिन्न इलाकों में बेच दिया गया जिसके सेवन से या तो लोगों की जान चली गई या उनके

गुर्दे खराब हो गए। पवन खेड़ा ने कहा एक ड्राई स्टेट में इतना सब कुछ हो जाए और स्थानीय पुलिस-प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सत्ताधारी दल के नेता, पुलिस-प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत रही होगी। यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस आधार भी है। रोजीद गांव के सरपंच ने प्रशासन को लगातार पत्र लिखकर बताया कि गांव में सरेआम देसी शराब की बिक्री की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों ने साफ बताया है कि कोई शराबबंदी नहीं हुई है। गुजरात में अवैध शराब का करीब 15,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है। पीएम नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर से लेकर हर ज़िले में शराब का ग़ैर क़ानूनी धंधा फल फूल रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि इतना बड़ा मामला हुआ, करीब 50 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न गृहमंत्री और न मुख्यमंत्री सामने आए हैं और न प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों से मुलाक़ात की, जबकि प्रधानमंत्री गुजरात में ही हैं। उन्होंने कहा जहरीली शराब कांड की उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप है यदि वही जांच करेगी तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकतर गरीब थे और घर चलाने की उन पर जिम्मेदारी थी। ऐसे परिवारों को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

यूक्रेन और चीन से लौटने को मजबूर हुए मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने जा रही है भारत सरकार

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि मेडिकल के अंतिम वर्ष के उन छात्रों को एफएमजी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत लौटे हैं और जिन्हें अधिसूचना तिथि पर डिग्री प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने 23 जून को एक हलफनामे में कहा कि विदेशी चिकित्सा स्नातक (एफएमजी) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे विदेशी चिकित्सा स्नातकों को मौजूदा एक साल के मानदंड के बजाय दो साल के लिए कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) करनी होगी। विदेशी चिकित्सा स्नातक दो वर्ष तक सीआरएमआई पूरा करने के बाद ही पंजीकरण के पात्र होंगे। एनएमसी के हलफनामे में कहा गया है कि क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए इंटर्नशिप की अवधि को दोगुना कर दिया गया है ।

एनएमसी के रुख पर गौर करते हुए, शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई के आदेश में कहा, %23 जुलाई के हलफनामे के साथ दायर अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जाता है। वर्तमान में विभिन्न आवेदनों के सिलसिले में आगे कोई आदेश देने की अपील नहीं जा सकती। तदनुसार आवेदनों का निपटारा किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उसका भी निपटारा किया जाता है।% उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल को नियामक संस्था को रूस-यूक्रेन युद्ध और महामारी से प्रभावित एमबीबीएस छात्रों को एक बार के उपाय के रूप में यहां के मेडिकल कॉलेजों में अपना क्लीनिकल प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति देने के लिए दो महीने में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

एनएमसी ने हलफनामे में कहा कि 29 अप्रैल के फैसले के बाद, उसके स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी) ने अपनी विभिन्न बैठकों में विदेशी चिकित्सा स्नातकों से संबंधित मामले पर चर्चा की और विचार-विमर्श किया। यूजीएमईबी के सदस्यों, स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के दौरान, यह बताया गया कि यूक्रेन के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 20,672 भारतीय छात्र नामांकित हैं, जो ऑनलाइन

कक्षाएं ले रहे हैं। एनएमसी ने हलफनामे में कहा कि मेडिकल के अंतिम वर्ष के उन छात्रों को एफएमजी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत लौटे हैं और जिन्हें अधिसूचित होने की तिथि पर डिग्री प्राप्त हुई है। इनमें वे छात्र भी शामिल हैं, जो कोविड-19 के कारण चीन से लौटे हैं।

श्रीलंका : ध्वज का अपमान करने के आरोप में श्रमिक संगठन का नेता गिरफ्तार

कोलंबो। श्रीलंका में एक श्रमिक संगठन के नेता को राष्ट्रपति कार्यालय में अवैध तरीके से प्रवेश करने और राष्ट्रपति के ध्वज को चादर की तरह उपयोग करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। यह घटना करीब तीन सप्ताह पहले की है, जब पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोग जबरन राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर गए थे। 'डेली मिरर' अखबार की खबर के अनुसार, 54-वर्षीय आरोपी की पहचान उडेनी कलुतंतरी के रूप में हुई है, जो एक बंदरगाह पर सुरक्षा अधिकारी है। उडेनी को कोलंबो के डैम स्ट्रीट थाने में आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तार किया गया। खबर के अनुसार, उडेनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उसे राष्ट्रपति के आधिकारिक ध्वज को बिस्तर की चादर के तौर पर उपयोग करते देखा जा सकता है। श्रीलंका पुलिस ने कहा कि उडेनी को राष्ट्रपति कार्यालय में अवैध तरीके से प्रवेश करने और राष्ट्रपति के ध्वज को चादर की तरह उपयोग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

रूस में व्हाट्सऐप और स्नैपचैट पर जुर्माना लगाया गया

लंदन। रूस के नियामकों ने ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयासों के तहत रूसी उपयोगकर्ताओं का डेटा लोकल सर्वर में नहीं रखने के लिये व्हाट्सऐप और स्नैपचैट पर जुर्माना लगाया है। मॉस्को की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को व्हाट्सऐप पर 1 करोड़ 80 लाख रूबल (तीन लाख डॉलर) और स्नैपचैट पर 10 लाख रूबल का जुर्माना लगाया है। रूसी संचार नियामक रोस्कोमनादजोर की शिकायत पर यह जुर्माना लगाया गया है। रूसी सरकार कई वर्ष से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर व्यापक नियंत्रण का प्रयास कर रही है। हाल के महीनों में यह प्रयास तेज हुआ है क्योंकि सरकार यूक्रेन के बारे में संचार प्रवाह को सीमित करने की कोशिश कर रही है।

मेक्सिको : ट्रेलर ट्रक में ठुंसे हुए थे 94 प्रवासी, कंटेनर में छेद कर सभी ने बचाई अपनी जान

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको के वेराक्रूज में एक राजमार्ग पर प्रवासियों से भरे एक मालवाहक ट्रेलर ट्रक को बीच रास्ते में छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसमें मौजूद 94 प्रवासियों ने किसी तरह खुद को बचाया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। खाड़ी तटीय राज्य वेराक्रूज में प्रवासियों संबंधी मामलों के कार्यालय के प्रमुख कार्लोस एनरिक एस्केलांटे ने बताया कि प्रवासियों ने बाहर निकलने के लिए मालवाहक कंटेनर में छेद किया और कुछ लोग कंटेनर की छत से बाहर आए। कंटेनर की छत से छलांग लगाने से कुछ प्रवासी घायल हो गए, हालांकि इसमें किसी को कोई घातक चोट नहीं आई। एस्केलांटे ने बताया कि अकायुकान शहर के पास के स्थानीय निवासियों ने शोर सुना और मालवाहक कंटेनर को खोलने में मदद की। माना जाता है कि ट्रेलर में बड़ी संख्या में प्रवासी सवार थे और कंटेनर से निकलने के बाद कुछ प्रवासी भाग गए। ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर के 94 प्रवासियों को आव्रजन अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। बुधवार को सामने आए इस मामले ने 27 जून को टेक्सास के सैन एंटोनियो में हुई उस त्रासदी की यादें ताजा कर दीं, जब एक मालवाहक ट्रक में छोड़े गए 53 प्रवासियों की मौत हो गई थी।

बादलों में दिखी रहस्यमयी लाल रोशनी, वीडियो को देखकर लोगों ने कहा- खत्म होने वाली है दुनिया?

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो को देखकर लोग अपने विचार और कयास लगाते रहते हैं। इसी बीच एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसे देखकर लोग काफी चौंक गए हैं। इस वीडियो में एक पायलट बादलों की ओर इशारा करते हुए लाल रंग की रोशनी दिखाई। बादलों के बीच लाल रंग की रोशनी को देखकर कुछ लोग दुनिया खत्म होने का संकेत दे रहे है तो कुछ का कहना है कि ये काफी डरावना है। हालांकि, कुछ लोग इसके पीछे लॉजिक ढूंढते नजर आ रहे है। एक वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है अटलांटिक महासागर के ऊपर एक रहस्यमयी लाल चमक का वीडियो फुटेज। इस वीडियो को देखकर कई लोग डर गए हैं। किसी को नहीं समझ आ रहा कि इस लाल रोशनी के पीछे का राज क्या है। इस वीडियो को देखकर लोग काफी डर गए हैं। कई लोगों का कहना है कि यह एक तरीके का अटलांटिक सॉरी है जो कनाडा से बरमूडा तक और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में पाया जाता है। यहां जहाजों को पेरिमीटर के चारों ओर सैकड़ों लाल बत्तियों का इस्तेमाल करके मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता हैं। लोग इसे इस लाल रोशनी के साथ जोड़कर देख रहे है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। बता दें कि हजारों बार इस वीडियो को देखा जा चुका है।

गंभीर नकदी संकट से गुजर रहे चीनी बैंक, निकासी फीज करने से 4 लाख ग्राहक प्रभावित

हेनान। इनदिनों चीनी बैंक एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, यह देखकर शहर के कई स्थानीय बैंकों ने पैसों की निकासी को फीज कर दिया है। चीन ने ऐसा गंभीर नकदी सकंट से बचने के लिए किया है, लेकिन इससे अब बैंक के ग्राहकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। बता दें कि ग्राहकों ने अपने पैसे बैंकों में जमा कराए थे लेकिन अब वह इस चाह कर भी निकाल नहीं पा रहे हैं।इनदिनों चीनी बैकों की हलात बहुत खराब चल रही है। इसका कारण देश में कोरोना महामारी के मामले बढ़ना और रियल एस्टेट में मंदी आना है। इससे बैंकों को काफी नुकसान पहुंचा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रही है। चीनी शहर हेनान और अनहुई प्रांतों के स्थानीय बैकों से ग्राहक अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और यह देखकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन को शांत करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने काफी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। हेनान शहर में प्रदर्शनकारियों की कोरोना स्थिति को एक अनिवार्य फोन ऐप पर लाल रंग में सेट कर दिया है जिसके कारण उन्हें घर के अंदर ही रहने पर मजबूर होना पड़ा रहा है। सरकार के समर्थित गुंडें प्रदर्शनकारियों पर जमकर हमला भी कर रहे है, जिसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। बता दें कि बैकों द्वारा निकासी फीज कराने से लगभग 4,00,000 बैंक ग्राहक प्रभावित हुए हैं और इसमें 6 अरब डॉलर की राशि जमा है। बैंक पहले ही कोरोना महामारी से पैदा हुई आर्थिक मंदी झेल रहा है। हालांकि, सरकार ने ग्राहकों को छोटी निकासी लेने निकालने की अनुमति दे दी है। माना जाता है कि चीनी जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योग 17.5 ट्रिलियन डॉलर हैं। ज्यादातर चीन के मध्यम वर्ग के लोग निवेश के लिए इसको ही प्रमुख साधन मानते है। यहां तक की चीन बैकों के कुल कर्ज का एक तिहाई हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दिग्गज प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांडे ग्रुप को लोन डिफॉल्ट के कारण बड़ा झटका लगा और इससे कंपनी के शेयर में गिरावट आई थी।

ट्विटर का खुलासा, दुनियाभर की सरकारें यूजर अकाउंट की जासूसी करने को कह रही

वाशिंगटन। ट्विटर ने खुलासा किया कि दुनियाभर की सरकारें कंपनी से यूजर अकाउंट्स से सामग्री हटाने या उनके निजी विवरणों की जासूसी करने को कह रही हैं। कंपनी ने नई रिपोर्ट में खुलासा किया है, उसने पिछले साल छह महीने की अवधि के दौरान स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारों की रिकॉर्ड 60,000 कानूनी मांगों पर कार्रवाई की। ये सरकारें चाहती थीं कि ट्विटर अकाउंट से या तो सामग्री हटाई जाए या कंपनी यूजर की गोपनीय जानकारी यथा-प्रत्यक्ष संदेश या यूजर के स्थान, का खुलासा करे। ट्विटर की सुरक्षा और अखंडता मामलों के प्रमुख ने कहा, हम देख रहे हैं, कि सरकारें हमारी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों को बेनकाब करने के लिए कानूनी रणनीति का उपयोग करने, अकाउंट के मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने और कानूनी मांगों का उपयोग करने की कोशिश करने और लोगों को चुप कराने के तरीके के रूप में अधिक आक्रामक होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से सबसे अधिक 20 प्रतिशत अनुरोध आए, जिसमें अकाउंट की जानकारी, उसकी सूचना मांगी गई थी, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे है। ट्विटर का कहना है कि उसने मांगी गई सूचना के हिसाब से लगभग 40 प्रतिशत यूजर के अकाउंट की जानकारी साझा की। जापान की ओर से अकाउंट की जानकारी पाने का अनुरोध होता रहा हैं, और वह अकाउंट से सामग्री हटाने के लिए ट्विटर से सबसे अधिक अनुरोध करता है। सामग्री को हटाने के लिए जापान ने सभी अनुरोधों का आधा 23,000 से अधिक अनुरोध किए। रूस भी इसमें पीछे नहीं रहा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक मेटा ने भी इसी समय सीमा के दौरान सरकार द्वारा निजी यूजर डेटा की मांग में वृद्धि की सूचना दी।

दक्षिण कोरिया में आठ हजार टन से ज्यादा भारी जहाज तैयार नजर आया।

कनाडा में पोप फ्रांसिस का दौरा, यौन शोषण पर कार्रवाई की मांग

- फ्रांसिस ने कनाडा के एक तीर्थस्थल में स्वदेशी समूहों के साथ उत्सव में भाग लिया

ओटावा । कैथोलिक चर्च द्वारा चलाए जा रहे आवासीय स्कूलों में दशकों से चली आ रही दुर्व्यवहार के पीड़ितों से माफी मांगने के लिए पोप फ्रांसिस अपने प्रायश्चित यात्रा के लिए कनाडा रवाना हुए थे। फ्रांसिस ने कनाडा के एक तीर्थस्थल में स्वदेशी समूहों के साथ उत्सव में भाग लिया। वहां पोप को देखने के लिए हजारों की संख्या में स्वदेशी लोग एकत्रित हुए थे। मनोवैज्ञानिक आघात को ठीक करने के लिए कई पारंपरिक उपाय भी किए गए। एक समूह ने कनाडा के स्वदेशी लोगों के खिलाफ की गई गालियों का विरोध करते हुए एक बैनर भी रखा। वहीं पीड़ितों का कहना है कि माफी पर्याप्त नहीं है। यह आघात पीढ़ियों से चला आ रहा है। पोप की माफी, कई लोगों के लिए भारी रही है। पीड़ितों ने यौन शोषण अपराधों पर कार्रवाई की मांग की है। स्वदेशी नेताओं ने सदियों बाद सिद्धांत और आवासीय विद्यालयों के गठन के बीच एक सीधी रेखा खींची है। कनाडा में पोप ने बताया कि आवाज उठाई जा रही है। लगभग 150,000 फर्स्ट नेशन्स, मेटिस और इनुइट बच्चों को 1800 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक पूरे कनाडा में 139 आवासीय स्कूलों में नामांकित किया गया था, जो कि जबरन आत्मसात करने की सरकारी नीति के हिस्से के रूप में था। उन्हें अपनी मातृभाषा तक बोलने नहीं दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान करीब 6 हजार बच्चे मारे गए थे।

मंकीपॉक्स के प्रकोप को रोका जा सकता है: डब्ल्यूएचओ

- 78 देशों से डब्ल्यूएचओ के सामने अभी तक मंकीपॉक्स के 18,000 से ज्यादा मंकीपॉक्स के मामले आए

वाशिंगटन (एजेंसी)।

मंकीपॉक्स के मामलों को बढ़ता देख विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर संक्रमित देश, समुदाय और व्यक्ति खुद को इस बीमारी के बारे में जागरुक करते हैं और लोगों में इसके संचरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं तो मंकीपॉक्स के प्रकोप को रोका जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि 78 देशों से डब्ल्यूएचओ के सामने अभी तक मंकीपॉक्स के 18,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक मामले यूरोपीय क्षेत्र से और 25 प्रतिशत अमेरिका के क्षेत्रों से रिपोर्ट किए गए हैं। अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 फीसदी संक्रमित मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। यह एक ऐसा संक्रमण है जिसे रोका जा सकता है अगर देशों, समुदाय और लोग खुद को इसके बारे में जागरुक करें और इसे रोकने के कदमों को गंभीरता से लें।

उन्होंने कहा कि मंकीपॉक्स के प्रकोप को रोकने का सबसे अच्छा तरीका इसके जोखिम को कम करना, यानी अपने साथ दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचना। इसमें वे पुरुष भी शामिल हैं, जो दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध

बनाते हैं। उन्हें अपने यौन पार्टनर्स की संख्या को कम करने, नए पार्टनर्स के साथ यौन संबंध पर पुनर्विचार करने और नए पार्टनर का कॉन्टेक्ट नम्बर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने उनसे से संपर्क किया जा सके। हालांकि, जो भी मंकीपॉक्स वायरस के संपर्क में आएगा संक्रमित हो जाएगा। यही वजह है कि डब्ल्यूएचओ देशों से आग्रह कर रहा है कि वे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और इम्यूनोसप्रेस्ड लोगों सहित अन्य कमजोर समूहों में संचरण के जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई करें।

यौन संपर्क के माध्यम से तो यह फैल ही सकता है लेकिन इसके अलावा, मंकीपॉक्स घरों में भी फैल सकता है, जैसे कि एक दूसरे को गले लगाना, चूमना और एक दूसरे का दूषित तौलिया या बिस्तर का इस्तेमाल करना। जो लोग मंकीपॉक्स के संपर्क में आते हैं उनके लिए डब्ल्यूएचओ टॉर्गेट वैक्सीनेशन की सलाह देता है। साथ ही उन लोगों के लिए भी जिनमें इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। इसमें कई यौन पार्टनर्स रखने वाले लोगों के अलावा, स्वास्थ्य कर्मी और लैब कर्मी भी शामिल हैं, ताकि वे मरीज़ की देखभाल के दौरान खुद को सुरक्षित रख सकें। साथ ही उन्होंने साफ किया कि डब्ल्यूएचओ सभी की वैक्सीन लगाने की सिफारिश नहीं कर रहा है।

पुतिन की तबीयत खराब, निकोलाई पेत्रुशेव बन सकते हैं नए राष्ट्रपति

-यूके की विदेशी खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख का दावा

लंदन (एजेंसी)।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खराब तबीयत के बीच यूके की विदेशी खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख ने रूस के संभावित नए राष्ट्रपति का नाम बताया है। सर रिचर्ड डियरलोव के मुताबिक रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव रूस के मौजूदा राष्ट्रपति की जगह ले सकते हैं।डियरलोव ने रूस के संभावित नए राष्ट्रपति पर चर्चा की। डियरलोव की टिप्पणी उस समय आई है जब दावा किया जा रहा है कि रुसी राष्ट्रपति का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है।

डियरलोव ने कहा कि निश्चित रूप से पेत्रुशेव रूसी राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन वह कितने समय तक राजनीतिक रूप से सक्रीय रहते है, यह एक दूसरा सवाल होगा। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में यह अफवाह जोर पकड़ रही है कि 69 वर्षीय पुतिन खराब स्वास्थ्य या किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। हालांकि रूस ने इन बातों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पेत्रुशेव पुतिन के करीबी सहयोगी हैं, जिन्होंने यूक्रेन पर रुसी आक्रमण और युद्धग्रस्त देश में रूस के लक्ष्यों को सही ठहराने का प्रयास किया है। पुतिन की ही तरह, पेत्रुशेव भी सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा एजेंसी केजीबी में कार्य कर चुके हैं। रूस की सरकारी वेबसाइट के अनुसार रूस की सुरक्षा परिषद राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय का एक अलग विभाग है। पेत्रुशेव इसी सुरक्षा परिषद के ही सचिव हैं। अगर रूस में कोई नया राष्ट्रपति आता है, तब वह देश में पुतिन के मजबूत दो दशकों के शासन के बाद सत्ता संभालेगा। रूस के नए कानून के तहत अभी पुतिन दो बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर उनकी सेहत सही रही, तब पुतिन रूस की कमान 2036 तक संभालते रहने वाले है।

श्रीलंका के बाद बांग्लादेश पर आया आर्थिक संकट, आईएफएम से मांगा लोन

-राहुल गांधी ने बांग्लादेश की थी तारिफ

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

ढाका (ईएमएस)। भारत के पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट छाया हुआ है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और अब बांग्लादेश के आर्थिक हालात बिगड़ने की खबर है। कोरोना और रूस-यूक्रेन युद्ध ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। बता दें कि वित्तीय संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश ने वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएफएम) से 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मांगा है, इससे साफ होता है, कि बांग्लादेश आर्थिक मुसीबतों से जूझ रहा है।

2020 तक बांग्लादेश की पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही थी। यह अनुमान लगा रहा था कि बांग्लादेश आने वाले समय में जीडीपी को लेकर भारत को पीछे छोड़ देगा। जिसके बाद से भारत के विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया कि बीजेपी सरकार पिछले 6 साल से नफरत कि राजनीति कर रही है, यही मोदी सरकार की उपलब्धि है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे इस देश ने अपने हालतों पर काबू पा लिया। लेकिन अब फिर से बांग्लादेश पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन 1.25 डॉलर में अपना जीवन चलाने वाले लोग 2019 में 9 फीसदी ही रह गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में आयत-निर्यात के बीच काफी अंतर बढ़ा है। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि आयत में तेजी आई है, लेकिन निर्यात घटा है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई, 2021 से लेकर मई 2022 के बीच 81.5 अरब डॉलर का आयात किया गया था यदि इसकी तुलना बीते साल से की जाए तो आयात में 39 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका अर्थ है कि बांग्लादेश ने दूसरे देशों से सामान मंगवाने में अधिक डॉलर खर्च किए हैं और विदेशों को अपने सामान का निर्यात कम किया है जिससे देश के खजानों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है।

मेरी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना व ईंधन संकट दूर करना है : विक्रमसिंघे

कोलंबो (एजेंसी)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता देश आर्थिक संकट से बाहर निकालकर पटरी पर लाना और देश में व्याप्त ईंधन संकट को खत्म करना है। श्रीलंका को आखिरी बार ईंधन की खेप भारत ने जून में ऋण सहायता के रूप में भेजी थी, जिसके बाद से श्रीलंका में ईंधन की किल्लत और बढ़ गई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपने पार्टी मुख्यालय में एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है और बशर्ते कानून न तोड़ा जाए। हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं और हम मिलकर परस्पर सहयोग से ही इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे मुश्किल दौर में राष्ट्रपति बना हूं।

उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकार का पहला कार्य ईंधन के लिए लगने वाली कतार को कम करना और फिर उसे पूरी तरह से खत्म करना है। गौरतलब है कि 27 जून से सरकार ने ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी और इसे आवश्यक सेवाओं के लिए सीमित कर दिया। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकरा ने कहा कि श्रीलंका अगले 12 महीने तक ईंधन के आयात को सीमिति रखेगा, क्योंकि देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी है।

उन्होंने पूरे देश में ईंधन के लिए राशन व्यवस्था भी लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा ईंधन की दैनिक मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए क्यूआर कोड प्रणाली लागू की गई है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन के आयात पर अगले 12 महीने तक पाबंदियां रहेंगी।

ऋषि सुनक बोले- ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद एनर्जी बिल पर वेट टैक्स को कर देंगे समाप्त

लंदन (एजेंसी)।

ब्रिटेन में इन दिनों प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचार अभियान में उम्मीदवार आम जनता को रिझाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लिज़ ट्रस और ऋषि सुनक में टक्कर है। पीएम की रेस में ऋषि इस समय पीछे चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो शीतकालीन योजना के हिस्से के रूप में घरों द्वारा भुगतान किए गए एनर्जी बिल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (वेट) को खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स को लेकर उनकी नीतियों में ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि शुरुआत से ही सुनक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वह लुभाने वाली पॉलिसी से दूर रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वेट के हटने से साल भर में औसत घरेलू उपभोक्ताओं को 160 पाउंड लगभग 15,500 रुपए की बचत होगी। तीन महीने पहले वित्त मंत्री रहने के दौरान ऋषि सुनक ने उर्जा बिलों में कटौती से इनकार किया था। उस दौरान उन्होंने कहा कि ये परिवारों के लिए एक बड़ी मदद नहीं होगी।

चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दी खुली चेतावनी, कहा- ताइवान के मुद्दे से रहें बिल्कुल दूर

वाशिंगटन (एजेंसी)।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने फोन पर बातचीत के दौरान अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडन को ताइवान को लेकर उसके मामले में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी। ताइवान स्वशासित द्वीप है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। शी और बाइडन के बीच बृहस्पतिवार को फोन पर तीन घंटे हुई बातचीत की जानकारी देते हुए चीन सरकार ने बताया कि शी ने देश की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को विभाजित किए जाने के खिलाफ भी सचेत किया। व्यवसायियों एवं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चीनी औद्योगिक नीतियों और प्रौद्योगिकी निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा लाए एक बदलाव नवाचार को धीमा करके और लागत में वृद्धि करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच, अमेरिका के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि शी और बाइडन व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने की संभावना तलाश रहे हैं। शी को जी20 देशों की बैठक के लिए नवंबर में इंडोनेशिया आमंत्रित किया गया है और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच सामने-सामने की मुलाकात होने की संभावना है। चीन सरकार ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया किया कि क्या शी और बाइडन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की संभावित यात्रा पर चर्चा की या नहीं, लेकिन शी ने ऐसी ''बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप'' को खारिज कर दिया, जो ताइवान को अपनी दशकों पुरानी स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। बयान में कहा गया, ''चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना 1.4 अरब से अधिक चीनी लोगों की दृढ़ इच्छा है। आग से खेलने वाले लोग स्वयं जलकर खाक हो जाएंगे।'' शी का यह कड़ा बयान संकेत देता है कि चीनी नेताओं का संभवत- यह मानना है कि वाशिंगटन को ताइवान को लेकर पहले दी गई चीन की चेतावनियों की गंभीरता समझ नहीं आई है। इससे पहले, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बुधवार को पेलोसी की प्रस्तावित ताइवान यात्रा को लेकर चेतावनी दोहराई। पेलोसी अगर ताइवान की यात्रा करती हैं तो 1997 के बाद किसी

शीर्ष अमेरिकी निर्वाचित प्रतिनिधि की इस द्वीपीय देश की पहली यात्रा होगी। चीन के सरकारी बयान के अनुसार, शी ने आर्थिक मंदी के जोखिम को कम करने, समिष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों में समन्वय करने एवं कोविड-19 से निपटने जैसे क्षेत्रों में सहयोग किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने रणनीतिक कारणों से अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्थाओं को अलग के खिलाफ भी सचेत किया।